राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 198 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरूवार ,07 जनवरी 2021, मूल्य रु. 1.50

संक्षिप्त समाचार

अन्नदाता और सरकार के मध्य सहमति से रास्ता निकलना चाहिए : रामदेव

हरिद्वार, (एजेंसी)। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि देश में चल रहे किसान आंदोलन में अन्नदाता और सरकार के मध्य आपसी सहमति से बीच का रास्ता निकलना चाहिए। पतंजलि योगपीठ के 26वें स्थापना दिवस पर बाबा रामदेव ने कहा कि किसानों की आड़ में कुछ शरारती तत्व अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं, इन लोगों से किसानों को बचना चाहिए। उन्होंने कहा, आपसी संवाद से जल्द समाधान निकल जाएगा। कोरोना टीके के संबंध में रामदेव ने कहा कि इसमें नहीं गाय का खून है और न ही सुअर की चर्बी है।

बिहार कांग्रेस में बगावत के आसार

पटना, (एजेंसी)। बिहार में सियासी उठापटक फिर तेज हो गई है। बिहार कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया है कि पार्टी के 11 विधायक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से जुड़ सकते हैं। उन्होंने सभी विधायकों के नाम विधायक दल के नेता को बता दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी इनमें शामिल हैं। उनके इस दावे से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है।

ओम बिरला पंचायती राज संस्थाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे

बंदेमातरम संवाददाता

नई दिल्ली। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर और पंचायत सदस्यों को संसद के कार्यकरण और लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं भावनाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से देश की पंचायती राज संस्थाओं के लिए 8 जनवरी, 2021 को देहारादून, उत्तराखंड में एक परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है । लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, उत्तराखंड विधान सभा के अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे।

इस कार्यक्रम का विषय पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का सशक्तीकरण है।

देशभर में बढ़ा बर्ड फ्लू का खौफ

नई दिल्ली/भोपाल, (एजेंसी)। देश में कोरोना का असर कम हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में बर्ड फ्लू का असर बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर बुधवार को आला अफसरों के साथ आपात बैठक की। इसमें फैसला लिया गया कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से सीमित अवधि के लिए पोल्ट्री का व्यापार प्रतिबंधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अस्थाई रोक एहतियातन लगाई गई है। प्रदेश के तीन जगहों इंदौर, आगर-मालवा और मंदसौर में सैकड़ों कौवों की मौत के बाद सावधानी बरती जा रही है। हालांकि वर्तमान में प्रदेश में इसको लेकर संकट जैसी स्थिति नहीं है, बस बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं।

बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर जिलों में गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश जारी करेगा। इसके साथ ही पशुपालन विभाग और सहयोगी एजेंसियों को इस मामले में सजग रहने, रैंडम जांच करने और लोगों को आवश्यक जानकारी देने का निर्देश है। स्वास्थ्य विभाग के एक अफसर ने बताया कि मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने रोज जानकारी लेने के लिए दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बनाया है।

मध्यप्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी 2021 तक इंदौर में 142, मंदसौर में 100, आगर-मालवा में 112, खरगोन जिले में 13 और सीहोर में नौ कौवों की मौत हुई है। मृत कौवों के नमूने तुरंत भोपाल स्थित स्टेट डीआई लैब भेजे जा रहे हैं।

जिलों में तैनात पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कौवों की मौत की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और अन्य विभागों के समन्वय से तुरंत नियंत्रण और शमन की कार्यवाही कर रिपोर्ट भेजें। पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मार्केट, फार्म, तालाब और प्रवासी पक्षियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। प्रवासी पक्षियों के नमूने भोपाल लैब को भेजें।

पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि नियंत्रण कार्य में लगे अमले को पीपीई किट, एंटी वायरल ड्रग, मृत पक्षियों, संक्रमित सामग्री, आहार का डिस्पोजल और डिसइन्फेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कौवों में पाया जाने वाला वायरस एच5एन8 अभी तक मुर्गियों में नहीं मिला। मुर्गियों में पाया जाने वाला वायरस एच5एन1 होता है। लोगों से अपील है कि पक्षियों की मौत की सूचना तुरंत स्थानीय पशु चिकित्सा संस्था या पशु चिकित्सा अधिकारी को दें।

देशभर में 10 दिन में 4.84 लाख 775 पक्षियों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालयान के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है, जो राज्यों के साथ संपर्क में रहेगा।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में वीडियो-टेलीकांफ्रेंस के माध्यम से संघीय गणतंत्र जर्मनी की एंजेला मर्केल के साथ बातचीत करते हुए।

किसानों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कृषि कानूनों के विरोध में 40 दिनों से धरना दे रहे किसानों और सरकार के बीच सात दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई अंतिम नतीजा नहीं निकल सका है। इस बीच सुर्कीम कोर्ट ने किसानों की हालत पर चिंता जताई है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग और किसानों के प्रदर्शन को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्न ने 11 जनवरी तक स्थगित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसानों के विरोध के संबंध में जमीन पर कोई सुधार नहीं हुआ है, केंद्र द्वारा कहा गया था कि इन मुद्दों को लेकर सरकार और किसानों के बीच स्वस्थ चर्चा चल रही है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस बात की अच्छी संभावना है कि निकट भविष्य में सरकार और किसान किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली दलीलों पर केंद्र द्वारा प्रतिक्रिया दायर करने से किसानों और सरकार के बीच बातचीत में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित करते हुए कहा कि सरकार और किसानों के बीच स्वास्थ वातावरण में बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि इन मामलों को 8 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। उधर, किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के भाजपा नेताओं नेप्र पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद भाजपा नेताओं ने इस मामले के जल्द समाधान की उम्मीद जताई। प्रदर्शनकारी किसानों में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के ही हैं। पंजाब के भाजपा नेता सुरजीत कुमार ज्याणी और हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को किसान आंदोलन से जुड़े एक-एक चीज की जानकारी है।

बढ़ी नीरव मोदी की दिक्कतें, बहन मामले में बनी सरकारी गवाह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला में भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल पीएनबी घोटाले में भगोड़ा नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी को सरकारी गवाह बनाने के लिए स्पेशल कोर्ट ने इजाजत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत मामलों को देखने वाले विशेष न्यायाधीश वीसी बर्डे ने सरकारी गवाह बनने को लेकर पूर्वी के दिए आवेदन को स्वीकार कर लिया। आदेश मंगलवार को उपलब्ध हुआ। अदालत ने कहा कि मामले में माफी मांगने के बाद आरोपी पूर्वी मोदी (पूर्वी अग्रवाल) अब सरकारी गवाह होगी। बेल्जियम की नागरिक पूर्वी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में आरोपी है। अदालत ने आदेश में कहा, आरोपी फिलहाल विदेश में रह रही है। उस अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाएगा। इसके लिए अभियोजन पक्ष जरूरी कदम उठाएगा। अपने माफी आवेदन में पूर्वी मोदी ने कहा कि वह मुख्य अभियुक्त नहीं है और जांच एजेंसियों ने उसकी सीमित भूमिका ही बताई है। उसने कहा कि जरूरी सूचना और दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए प्रवर्तन निदेशालय के साथ पूरी तरह से सहयोग किया है।

उप्र में निर्भया कांड जैसी वारदात

बदायूं, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के बदायूं में निर्भया कांड जैसा मामला सामने आया है। यहां एक आंगनवाड़ी सहायिका की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। उनकी उम्र 50 साल थी। पोस्टमॉर्टम में उनके शरीर में गंभीर चोटें पाई गई हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि, अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पोस्टमॉर्टम में महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड जैसी भारी चीज डालने की पुष्टि हुई है। बाईं पसली, बाएं पैर और बाएं फेफड़े पर भी वजनदार चीज से हमला करने की बात सामने आई है।

घटना उचैती थाना इलाके के एक गांव की है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि महिला हर दिन की तरह रविवार को भी नजदीक के गांव के मंदिर में पूजा करने गई थीं। यहां मंदिर के पुजारी, उनके एक चेले और ड्राइवर ने महिला से दुष्कर्म किया। इसके बाद हत्या कर दी। देर रात पुजारी अपनी जीप से आया और दरवाजे पर महिला का शव फेंककर चला गया।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उचैती के थानेदार रावेंद्र प्रताप सिंह ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। मौके का मुआयना भी नहीं किया। घटना के करीब 18 घंटे बाद सोमवार दोपहर में लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में एसएसपी संकल्प शर्मा का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगाई गई हैं।

भारत वहां उत्पाद बनाना चाहता है, जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो : मोदी

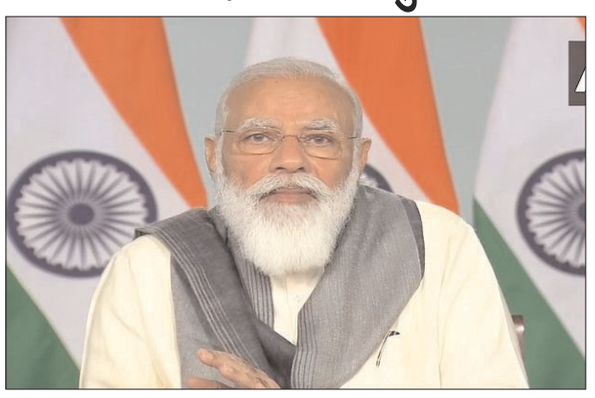

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर में किफायती, टिकाऊ और उपयोगी वस्तुओं की खोज की जा रही है और घरेलू और वैश्विक, दोनों स्तर पर अवसरों का लाभ उठाने के लिए विशाल बाजार प्रतीक्षा कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत उन उत्पाद को बनाना चाहता है, जिनकी गुणवत्ता अच्छी हो और जिनकी विश्व स्तर पर तारीफ हो। मोदी ने एक पोस्ट में सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में अपने विचार साझा कर कहा कि इसमें गुणवत्ता पर उतना ही जोर है, जितना उत्पादन के पैमाने पर है। उन्होंने कहा, आज, दुनिया हमारा बाजार है। भारत के लोगों में क्षमता है। एक राष्ट्र के रूप में दुनिया भारत को भरोसेमंद देश मानती है।

उन्होंने कहा कि अपने लोगों की योग्यता और भरोसे के साथ भारत के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद दुनिया भर में पैठ बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सच्चा कदम होगा और वैश्विक समृद्धि को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय माप-पद्धति सम्मेलन में अपने संबोधन की मुख्य बातों को भी साझा किया, जहां उन्होंने भारतीय उत्पादों के लिए मात्रा के साथ ही गुणवत्ता पर भी जोर दिया था। मोदी ने कहा, भारत कौशल और प्रतिभा का एक ऊर्जा केंद्र है। हमारे स्टार्ट-अप उद्योग की सफलता हमारे युवाओं के उत्साह को दिखाती है। नए उत्पादों और सेवाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता मानकों के दोहरे सिद्धांत पर टिका हुआ है, और भारत अधिक उत्पादन करना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही वह ऐसे उत्पाद बनाना चाहता है, जिनकी गुणवत्ता अच्छी हो।

प्रधानमंत्री ने कहा, भारत सिर्फ अपने उत्पादों से वैश्विक बाजारों को भरना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि भारतीय उत्पाद दुनिया भर में लोगों का दिल जीतें। उन्होंने विनिमार्ताओं और उद्यमियों से कहा, जब हम भारत में बनाते हैं (मेक इन इंडिया), तब हमारा उद्देश्य न केवल वैश्विक मांग को पूरा करना है, बल्कि वैश्विक स्वीकार्यता हासिल करना भी है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप किसी भी उत्पाद या सेवा में जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट के बारे में सोचें।

भारत -चीन तनाव के बीच बढ़ेगी सेना की ताकत, सैनिकों को मिलेगा अमेरिका का ये खतरनाक हथियार

नई दिल्ली । चीन से सीमा पर तनाव के बीच भारतीय नौसेना को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। भारतीय और अमेरिकी रक्षा बलों के बीच सैन्य संबंध स्थापित करते हुए सौदा किया गया है। 3,800 करोड़ रुपये की इस समझौते के तहत कैलिबर बंदूकों से भारतीय नौसेना युद्धपोतों को लैस करेगी, जिससे नौसेना की ताकत पहले की तुलना में और अधिक बढ़ जाएगी। भारत ने 127 एमएम की 11 मीडियम कैलिबर बंदूकों को खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इश्यू किया है। ये गन भारतीय नौसेना के बड़े युद्धपोतों पर लगाई जानी हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि नई योजना के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट (एलओआर) जारी किया गया है। पहली तीन गन अमेरिकी नौसेना अपनी इंवेंटरी (स्टाक) से उपलब्ध कराएगी ताकि भारतीय युद्धपोतों को जल्द से जल्द इन गन से सुसज्जित किया जा सके। जैसे ही अमेरिका में नई गन का उत्पादन शुरू हो जाएगा और वे आपूर्ति के लिए तैयार होंगी तो भारतीय युद्धपोतों पर लगी अमेरिकी नौसेना की गन के स्थान पर नई गन लगा दी जाएंगी। भारतीय युद्धपोतों पर अमेरिकी नौसेना की बंदूकों को नए सिरे से बदला जाएगा। मध्यम कैलिबर बंदूकें भारतीय नौसेना में नई एंट्री होंगी और इस तरह की बंदूकों की तुलना में काफी अपग्रेड भी होंगी। पिछले चार सालों में भारतीय नौसेना ने अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ बहुत करीबी काम संबंध विकसित किए हैं, क्योंकि सैन्यबलों को ज्यादातर नए उपकरण अमेरिका से आ रहे हैं। टोही विमानों सहित सैन्य बलों में रूसी उपकरणों को पी -8 आई विमान से बदला गया है।

कृषि मंत्री तोमर ने कहा- कृषि कानून समर्थक किसानों की भावनाओं और हितों को समझें आंदोलकारी

नई दिल्ली। कृषि सुधार के लिए संसद से पारित तीनों कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले किसानों की संख्या बहुत बड़ी है। इसका हवाला देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आंदोलन करने वाले किसान यूनियन के नेताओं को कानून समर्थकों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। देश के किसान समुदाय की भावनाओं के मद्देनजर कृषि सुधार के कानून लाए गए हैं। कानून समर्थक किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए तोमर ने विश्वास जताया कि आंदोलनकारी संगठन सभी किसानों के हितों को देखते हुए सरकार के साथ वार्ता कर कोई समाधान जरूर निकालेंगे।

बुधवार को अखिल भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते संजय नाथ सिंह अपने प्रतिनिधियों के साथ तोमर से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने कानूनों के समर्थन में एक ज्ञापन कृषि मंत्री को सौंपा। प्रतिनिधियों ने सरकार को आंदोलनकारी किसान यूनियनों से वार्ता के लिए कुछ सुझाव भी दिए। संगठन ने काट्रैक्ट खेती वाले कानून के अमल में आने वाली गड़बड़ियों पर निगरानी रखने के लिए एक नियामक प्राधिकरण के गठन का सुझाव भी दिया।

मुलाकात के बाद तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। हम कानून समर्थक और विरोधी दोनों पक्ष के किसान संगठनों से बात कर रहे हैं। देश के कोने-कोने से किसान संगठनों के नेता यहां आकर कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। पत्र और टेलीफोन पर समर्थन मिलने का सिलसिला जारी है। हम उनका स्वागत करने के साथ धन्यवाद भी दे रहे हैं।

तोमर ने फिर भरोसा जताया कि आंदोलनकारी किसान संगठन कानून समर्थक किसानों की भावनाओं को समझेंगे। किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए वार्ता में किसी सर्वसम्मत समाधान पर पहुंचेंगे।

किसान नेताओं से बातचीत में कृषि मंत्री तोमर ने कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के प्रयासों का विस्तार से जिक्र किया। खासतौर पर छोटी जोत के किसानों के हित संरक्षण के लिए फार्म प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (एफपीओ) के गठन करने और कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के बारे में बताया।

उल्लेखनीय है कि आंदोलनकारी किसान संगठनों से सात चरणों की वार्ता हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। किसान संगठन अपने अड़ियल रुख के चलते जिद ठानकर बैठे हैं। वे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हैं। इन संगठनों का सितंबर से ही आंदोलन चल रहा है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं, ताकि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को लगता है कि सरकार मौजूदा एमएसपी और मंडी प्रणाली के खिलाफ है। कानूनी प्रावधानों से कारपोरेट सेक्टर को लाभ मिलेगा।

गणतंत्र दिवस परेड पर इस बार नहीं होंगे कोई मुख्य अतिथि

नई दिल्ली, (एजेंसी)। गणतंत्र दिवस परेड पर इस बार कोई विदेशी मेहमान सूत्रों ने दी है। इससे पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आमंत्रित थे लेकिन उन्होंने ब्रिटेन में फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से भारत दौरा रद्द कर दिया है। ब्रिटिन प्रशासन ने पीएम जॉनसन का दौरा रद्द होने की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और भारत नहीं जा पाने के लिए खेद व्यक्त किया है। साल 1993 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि थे। अगर बोरिस जॉनसन आते तो यह सम्मान पाने वाले वह दूसरे ब्रिटिश पीएम होते।

पीएम मोदी से बातचीत के दौरान ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने कहा कि जिस रफ्तार से ब्रिटेन में नया कोविड स्ट्रेन का प्रसार हो रहा है, उस लिहाज से मौजूदा दौर में उनका ब्रिटेन में रहना महत्वपूर्ण है, ताकि वह देश में वायरस संक्रमण की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। गौरतलब है कि ब्रिटेन में कोरोनावायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद वहां लॉकडाउन लगाया गया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। माना जा रहा है कि वायरस का नया वैरिएंट तेजी से संक्रमण फैलाता है।

नए वायरस के सामने आने के बाद कई देशों ने यात्रा संबंधी प्रतिबंध भी लगाए हैं। यात्रा पर अस्थायी बैन लगाने के बावजूद 30 से ज्यादा देशों में म्युटेंट वर्जन से संक्रमण के मामले पाए गए हैं। भारत में इस तरह के 58 मरीज मिले हैं। ये सभी मरीज या तो ब्रिटेन से आए हैं या फिर ब्रिटेन के यात्रियों के संपर्क में आए थे।

सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद का स्वागत करते हुए।

सऊदी जेल में बंद महिला अधिकार कार्यकर्ता लौजैन की रिहाई के लिए उठी आवाजें

दुबई, (एजेंसी)। सऊदी अरब में प्रिंस सलमान के शासनकाल में महिला अधिकार कार्यकर्ता लोजैन अल हथलोल को पिछले कुछ सालों के दौरान अमानवीय व्यवहार झेलना पड़ा। हाल ही में खबरें सामने आई थीं कि लोजैन को किस तरह अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए दमन और प्रताड़ना का शिकार बनाया गया।

अब महिला अधिकारों की आवाज उठाने वाली इस एक्टिविस्ट की रिहाई के समर्थन में दुनिया के कई हिस्सों से आवाज उठने लगी है और सऊदी अरब के रवैए के खिलाफ कई लोगों ने नाराजगी जताई है।

महिला अधिकारों के लिए लगातार सक्रिय रहने के लिए उन्हें नोबल पुरस्कार देने की भी पैरवी की गई है। सऊदी अरब में महिलाएं लिंगभेद की हमेशा से शिकार रही हैं। ऐसे में जब लोजैन ने व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई तो कुछ नियमों में तो बदलाव हुए, लेकिन इसकी कीमत लोजैन को चुकानी पड़ी। इसके लिए उन्हें गिरफ्तारी, नजरबंदी, धमकियों, प्रताड़नाओं यहां तक कि यौन शोषण और हत्या के खतरे का भी सामना करना पड़ा। पिछले दिनों सऊदी अरब की एक अदालत ने उन्हें आतंकवादी करार देकर करीब छह साल की कैद की सजा सुनाई। इस फैसले की दुनिया भर में प्रतिक्रिया हुई।

संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार वॉच और मानवाधिकारों से जुड़े कई विशेषज्ञों ने इस फैसले को निंदनीय बताया और आरोप लगाया कि सऊदी अरब का राज परिवार संदेह के घेरे में है। लोजैन की बहन लीना लगातार उनके साथ हो रहे दमनकारी सुलूक के विरोध में आवाज उठा रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीति मंचों तक वह लोजैन के लिए समर्थन जुटा रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अत्याचारों के खिलाफ कैद में रहते हुए लोजैन ने भूख हड़ताल की, लेकिन कोर्ट ने सब बातों को नजरअंदाज करते हुए लोजैन, अन्य एक्टिविस्टों और लोजैन के परिवार पर जुल्म करने वाले सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन के सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने लोजैन को दी गई सजा को न्याय विरुद्ध बताया और मानवाधिकारों के साथ खड़े होने की बात कही। पेरिस के मेयर एन हिडाल्गो ने लोजैन की तत्काल रिहाई की मांग की है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने लोजैन का समर्थन करते हुए उसकी जल्द रिहाई की मांग करते हुए उनके प्रति हमदर्दी जाहिर की है। जर्मनी की सांसद बारबेंल कोफलर ने सऊदी अरब के रवैए पर नाराजगी जताता और विरोध करता एक पूरा बयान जारी किया है। सऊदी अरब पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनने के बावजूद फिलहाल ऐसी खबर नहीं है कि लोजैन को रिहा करने पर विचार हो रहा है।

इंडोनेशिया काम करने वाले वयस्कों को पहले देगा वैक्सीन

जकार्ता, (एजेंसी)। इंडोनेशिया में कोविड-19 वैक्सीन देने की तैयारी शुरू हो चुकी है लेकिन उसकी योजना दूसरे देशों से अलग है। ज्यादातर देशों में वायरस की चपेट में आने के ज्यादा रिस्क वाले बुजुर्गों को वैक्सीन दी जा रही है। हालांकि, इंडोनेशिया ने फैसला किया है कि काम करने वाले वयस्कों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके जरिए तेजी से हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने की कोशिश की जाएगी और साथ ही अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाया जाएगा। इंडोनेशिया के इस कदम पर पूरी दुनिया की निगाहें भी टिकी हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देश वैक्सीन देना शुरू कर चुके हैं। यहां बुजुर्गों को वैक्सीन पहले दी जा रही है जिन्हें सांस संबंधी बीमारी होने का खतरा ज्यादा है। इंडोनेशिया में चीन की सिनोवेक बॉयोटेक की वैक्सीन देने की तैयारी की जा रही है। उसका कहना है कि अभी बुजुर्गों पर वैक्सीन के असर का पर्याप्त डेटा नहीं मिला है। देश में क्लिनिकल ट्रायल 18-59 साल के लोगों पर जारी है। अभी बुजुर्गों को वैक्सीन देने के बारे में देश के ड्रग रेग्युलेटर फैसला करेंगे। ब्रिटेन और अमेरिका में वैक्सीन दी जा रही है जो सभी उम्र के लोगों पर असरदार है।

इंडोनेशिया ने चीनी कंपनी के साथ 12.5 करोड़ खुराकों की डील की है जिसमें से 30 लाख खुराकें पहुंचाई जा चुकी हैं। फाइजर की वैक्सीन देश में तीसरी तिमाही में पहुंच सकती है जबकि ऑक्सफर्ड की वैक्सीन दूसरी तिमाही में। ऑस्ट्रेलियन नैशनल यूनिवर्सिटी के प्रफेसर पीटर कॉलिगनॉन का कहना है कि इंडोनेशिया के प्लान से बीमारी फैलने की रफ्तार धीमी हो सकती है लेकिन मृत्युदर पर ज्यादा असर की संभावना नहीं है। वहीं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में यॉन्ग लू लिन स्कूल के प्रफेसर डेल फिशर का कहना है कि युवा वयस्क ज्यादा सक्रिय होते हैं, ज्यादा सामाजिक होते हैं और सफर भी ज्यादा करते हैं। ऐसे में कम्यूनिटी ट्रांसमिशन को कम किया जा सकता है। वहीं देश के स्वास्थ्य मंत्री बूडी गुनाडी का कहना है कि देश को हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए 18.15 करोड़ लोगों को वैक्सिनेट करना होगा। उसे 42.7 करोड़ खुराकें चाहिए होंगी। हालांकि, हर्ड इम्यूनिटी पर और रिसर्च की जरूरत अभी है।

ओबामा सरकार ने दी थी अल-कायदा से जुड़े संगठन को फंडिंग : अमेरिकी रिपोर्ट

वाशिंगटन, (एजेंसी)। ओबामा प्रशासन और आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े संगठन की फंडिंग को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में ऐसा सनसनीखेज दावा किया गया है, जिससे अमेरिकी का राजनीति में भूचाल आ सकता है। अमेरिकी संसद समिति की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन ने जानबूझकर पैन-इस्लामिक प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-कायदा के एक सहयोगी को फंडिग की थी। रिपोर्ट सीनेट की वित्त समिति के अध्यक्ष चक ग्रासले (आर-आयोवा) के कार्यालय द्वारा ओबामा प्रशासन को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अप्रूवल के आधार पर जांच पर आधारित है।

ये फंड एक अमेरिकी सहायता संगठन वर्ल्ड विजन को अल-कायदा से एफीलेटेड इस्लामिक रिलीफ एजेंसी (इसरा) के लिए दिए जाने का आरोप है।

संयोग से वर्ल्ड विजन भारत में भी काम करता है और इंटरएक्शन का सदस्य है, जो अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठनों का सबसे बड़ा गठबंधन है। पिछले साल आईएएनएस ने एक बड़े खुलासे में बताया था कि कैसे अमेरिकी सरकार की एजेंसियां पाकिस्तान और मध्य पूर्व में स्थित इस्लामिक चैरिटीज को इंटरएक्शन के जरिए फंडिंग कर रही हैं। इंटरएशन के टुगेदर प्रोजेक्ट में सबसे विवादास्पद इस्लामिक चैरिटी शामिल हैं, जिसमें हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट (एचएचआरडी) शामिल है, जो कश्मीर में भारत के खिलाफ निर्देशित पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के धर्मार्थ और राजनीतिक विंग के साथ काम करता है।

अल्जीरिया में एक चिकित्साकर्मी दानदाताओं से एकत्र खून को दिखाती हुई।

अमेरिका में कोरोना से फिर बिगड़े हालात, 24 घंटों में रिकॉर्ड 3936 लोगों की मौत

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के अनुसार, अमेरिका में कोविड-19 से एक दिन में होने वाली मौतों का रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 3936 लोगों की मौत हुई है। उल्लेखनीय है कि दुनियाभर में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में हैं। अमेरिका में अब तक 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 3 लाख 57 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महामारी के शुरूआती दिनों में संभावना व्यक्त की थी कि उनके देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। तब ऐसा लगाता था कि शायद यह आंकड़ा काफी बड़ा है, लेकिन अब अमेरिका मौत के इस आंकड़े से बेहद आगे निकल गया है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के आने के बाद आंकड़ा अब कहां जाकर रुकेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।

उल्लेखनीय है कि दुनियाभर में कोरोना मरीजों की संख्या आठ करोड़ 56 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आने के बाद आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इनमें से दो करोड़ आठ लाख से ज्यादा केस अकेले अमेरिका में हैं। इसके बाद भारत में एक करोड़ तीन लाख से ज्यादा मामले मिले हैं। ब्राजील में 77 लाख 53 हजार से अधिक पॉजिटिव केस पाए गए हैं और एक लाख 96 हजार से ज्यादा की मौत हुई है।

जैक मा से उपभोक्ताओं का डेटा लेना चाहती थी चीन सरकार, मना करने पर किया नजरबंद

बीजिंग, (एजेंसी)। चीन के तीसरे सबसे बड़े अरबपति और दुनिया में लाखों लोगों के आदर्श रहे अलीबाबा समूह के संस्थापक जैक मा पिछले दो माह से लापता हैं। जैक मा कहां हैं, इसको लेकर चीन सरकार ने चुप्पी साध रखी है, जबकि दुनियाभर में अटकलों का बाजार गर्म है। एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार चीन की कम्युनिस्ट सरकार जैक मा से उनके उपभोक्ताओं के डेटा लेना चाहती थी, जो अलीबाबा के संस्थापक के लिए दौलत की तरह बेशकीमती है।

उपभोक्ताओं के डेटा के लिए चीन सरकार जैक मा को बाध्य कर रही थी, जिसका वह लंबे समय से विरोध कर रहे थे। दरअसल, चीन के वित्तीय नियामक चाहते थे कि जैक मा की कंपनी एंट ग्रुप अपने करोड़ों ग्राहकों का कंज्यूमर क्रेडिट डेटा उसे सौंप दे। चीनी रेगुलेटर्स के इस दबाव और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विवाद के बाद जैक मा के पास बहुत कम ऑप्शन बचे थे। रिपोर्ट में चीनी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि चीन की सरकार को इस बात की चिंता थी कि जैक मा अपने बिजनस को लगातार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका ध्यान वित्तीय खतरे को नियंत्रित करने की ओर कम था जो कि देश का लक्ष्य है।

चीन के रेगुलेटर्स का कहना था कि एंट ग्रुप पर्सनल डेटा की मदद से व्यापार में इसका गलत फायदा उठा रहा है। जैक मा अपने अलीपे एप के जरिए लोगों को लोन दिलवाते थे और मध्यस्थ के रूप में पैसा कमाते थे जबकि कर्ज का सारा रिस्क बैंकों का होता था। इस ऐप को करीब 50 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। उनकी आदतों, उधार लेने की प्रवृत्ति और लोन चुकाने का पूरा डेटा जैक मा के पास है।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस बिजनस मॉडल से जैक मा को फायदा हो रहा था लेकिन इससे चीन के वित्तीय सिस्टम को खतरा पैदा हो सकता था। इसके बाद चीनी अधिकारियों ने जैक मा के बिजनस मॉडल को बदलने का प्रयास किया और डेटा पर उनके एकाधिकार को तोड़ना चाहा। उधर, एंट ग्रुप ने इस पर अभी कोई बयान नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि जैक मा ने डेटा देने से मना कर दिया था।

जैक मा ने चीन के ब्याजखोर वित्तीय नियामकों और सरकारी बैंकों की पिछले साल अक्टूबर में शंघाई में दिए भाषण में तीखी आलोचना की थी। जैक मा ने सरकार से आह्वान किया था कि ऐसे सिस्टम में बदलाव किया जाना चाहिए, जो बिजनेस में नई चीजें शुरू करने के प्रयास को दबाने का प्रयास करता है। उन्होंने वैश्विक बैंकिंग नियमों को बुजुर्गों लोगों का क्लब करार दिया था। इस भाषण के बाद चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी भड़क उठी। जैक मा की आलोचना को कम्युनिस्ट पार्टी पर हमले के रूप में लिया गया। इसके बाद जैक मा के दुर्दिन शुरू हो गए और उनके बिजनेस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने शुरू हो गए।

नवंबर महीने में चीनी अधिकारियों ने जैक मा को जोरदार झटका दिया और उनके एंट ग्रुप के 37 अरब डॉलर के आईपीओ को निलंबित कर दिया। वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक जैक मा के एंट ग्रुप के आईपीओ को रद्द करने का आदेश सीधा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से आया था। इसके बाद जैक मा से क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कहा गया कि वह तब तक चीन से बाहर न जाएं जब तक कि उनके अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को पूरा नहीं कर लिया जाता है।

लाई जियाओमिन को भ्रष्टाचार के आरोप में मिली मौत की सजा

बीजिंग, (एजेंसी)। चीन हाओरांग असैट्स मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व अध्यक्ष लाइ जियाओमिन को रिश्वत, भ्रष्टाचार और दो शादियां करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। तियानजिन सिटी की स्थानीय अदालत के अनुसार 2008 और 2018 के बीच लाई को कुल 1.79 बिलियन युआन (277 मिलियन डॉलर यानि 20,28,86,71,100 रुपये) रिश्वत लेने का दोषी पाया गया। फैसले में उनकी सभी निजी संपत्तियों को जब्त करने की बात कही गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इन दिनों अभियान चला रखा है1 2020 की शुरूआत में लाइ जियाओमिन ने राज्य टीवी की एक डॉक्यूमेंट्री में स्वीकार किया था कि उन्होंने नकद भुगतान को प्राथमिकता दी1 पुलिस ने उनके फ्लैट में छापा मारकर 200 मिलियन से अधिक युआन बरामद किए। 2018 में उनकी नजरबंदी के बाद उनके पास बड़ी संख्या में संपत्ति मिली, साथ ही उन्हें लक्जरी घड़ियों, कारों, सोने और एक कला संग्रह का मालिक पाया गया।

चीन में भ्रष्टाचार के लिए मृत्युदंड की सजा सामान्य नहीं है। हालांकि 2018 में शांक्सी प्रांत में एक पूर्व उप महापौर को मौत की सजा सुनाई गई थी। इस कदम से सरकारी कैडर और कॉरपोरेट अधिकारियों के बीच फैले भ्रष्टाचार पर सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ते कड़े रुख को साफ समझा सकता है। सरकार के भ्राष्टाचार पर सख्त रवैये को 15 लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों को दंडित किए जाने से भी समझा सकता है। 2016 में चीन ने भ्रष्टाचार से संबंधित मृत्युदंड के साथ आर्थिक दंड 1,00,000 युआन से 3 मिलियन युआन तक बढ़ा दी थी लेकिन कभी किसी को मृत्यदंड नहीं दिया गया।

शराब पीने से कोरोना वैक्सीन का असर होगा कम

लंदन, (एजेंसी)। अगर आप कोरोना वायरस वैक्सीन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो शराब से दूरी बनाना आपके लिए जरूरी होने वाला है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि शराब पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। उन्होंने सलाह दी है कि एक दिन पहले या बाद में शराब पीने से वैक्सीन का असर कम हो सकता है। जानकारी के मुताबिक इमर्जेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉ रॉन्क इखारिया ने ब्लड सैंपल पर एक्सपेरिमेंट किया है। शराब पीने से पहले और बाद में ये सैंपल लिए गए थे। उन्होंने पाया कि तीन गिलास शराब का असर साफ देखा गया जिनके कारण लिम्फोसाइट की संख्या 50 प्रतिशत कम हो गई थी।

व्हाइट ब्लड सेल्स में 20-40 फीसदी तक लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट होते हैं। इस प्रयोग में सामने आया है कि शराब पीने से शरीर में रहने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवियों पर असर पड़ता है जो हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से हमारे शरीर को बचाते हैं। इसकी वजह से हमारे खून में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में मौजूद लिम्फोसाइट ही वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए ऐंटीबॉडी बनाते हैं। इम्यूनॉलजिस्ट प्रफेसर शीना क्रूकशैन्क का कहना है कि इसकी वजह से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 वैक्सिनेशन के आसपास शराब से दूरी बनाकर रखें। लिम्फोसाइट वे सेल होते हैं जो यह तय करते हैं कि वायरस जैसे हमलावर के खिलाफ कैसे लड़ना है। रूसी वैज्ञानिक अलेक्सजेंडर गिनटसबर्ग के मुताबिक हम स्पूतनिक वी वैक्सीन लगाने से तीन दिन पहले और बाद तक शराब न पीने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि कई प्रयोग में ये समय दो महीने भी बताया गया है। एलेक्जेंडर गामालेया नेशनल सेंटर आफ एपिडेमीयोलाजी एंड माइक्रोबायलाजी मॉस्को में अध्यक्ष हैं और उन्हीं की देखरेख में वैक्सीन तैयार की गयी है।

गौरतलब है कि ब्रिटेन में फाइजर और आक्सफोर्ड-आस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी जा रही है जबकि अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन दी जा रही है। भारत में एक्सपर्ट कमिटी की सिफारिश के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टिट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भारत में इमर्जेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जायडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव-डी को तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। बता दें कि दुनिया भर के करीब 20 देशों में या तो किसी न किसी वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है या फिर इमरजेंसी वैक्सीनेशन शुरू भी हो चुका है।

वाशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतरे उनके समर्थक।

दक्षिण-पश्चिमी व पश्चिमी जिले में छह-छह केंद्रों पर हुआ ड्राई रन

नई दिल्ली, एजेंसी। कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी के बाद आयोजित हो रहे ड्राई रन (पूर्वाभ्यास) ने नए साल में लोगों को नई उम्मीद दी है। बुधवार को दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम जिले में 12 केंद्रों पर ड्राई रन हुआ, जहां कुल 300 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन देने का पूर्वाभ्यास किया गया। दक्षिण-पश्चिमी जिले के अंतर्गत डाबड़ी स्थित दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, नजफगढ़ स्थित राव तुला राम अस्पताल, द्वारका सेक्टर-2, नजफगढ़, बिजवासन व छावला स्थित दिल्ली सरकार डिस्पेंसरी में सुबह आठ बजे से ड्राई रन की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रत्येक केंद्र पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने का पूर्वाभ्यास किया गया।

सुबह आठ बजे द्वारका सेक्टर-12 स्थित बेन्सअप्स अस्पताल के सामने स्थित दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी में बने कोल्ड स्टोरेज से सभी केंद्रों के लिए 25-25 वैक्सीन के डोज को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में वैक्सीनेशन आफिसर डा. अजय ने बताया कि जिन 25 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन देने का पूर्वाभ्यास किया गया, उन्हें मंगलवार को मैसेज के माध्यम से इस बावत सूचना दी गई। बुधवार को जब वे केंद्र पर पहुंचे तो यहां उनका पहचान पत्र देखने के बाद शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और इसके बाद हाथों को सैनिटाइज कराया गया।

दस मिनट इंतजार कक्ष में बैठने के बाद सभी को बारी-बारी से वैक्सीन दी गई। वैक्सीन देने से पूर्व कोविन एप पर उपभोक्ताओं की जानकारी को अपलोड किया गया। वैक्सीन मिलने के बाद उपभोक्ताओं में नकारात्मक लक्षण न हो इसके लिए उन्हें चिकित्सकों के अवलोकन में रखा गया। आधे घंटे के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई। इस दौरान जिला उपायुक्त डा. नवीन अग्रवाल, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर डा. अंजना कौशल, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस आफिसर डा. विमल कौशल, एसडीएम द्वारका पंकज राय गुप्ता, एसडीएम नजफगढ़ विनय कौशिक, एसडीएम कपासहेड़ा मुकेश रजौरा, द्वारका के तहसीलदार भूप सिंह, अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बृजेश कुमार, अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दीपमाला, ड्राई रन के सुपरवाइजर डॉ. दीपक भास्कर व नर्सिंग आफिसर सुनील शर्मा व सरभजीत मौजूद रहीं।

अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार से पूछे सात सवाल

प्रफुल्ल राय (शिवालिक)

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने देश भर के अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई 59,000 करोड़ रुपये की पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट किया और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर दिल्ली के अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए केजरीवाल सरकार से सात सवाल पूछे हैं और आगाह भी किया है कि यदि अगले सात दिनों में इन सवालों के जवाब नहीं दिए गए, तो अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के साथ मिलकर भाजपा केजरीवाल सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश भाजपा के मीडिया विभाग के प्रमुख नवीन कुमार, प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र गोठवाल व पूर्व महापौर योगेंद्र चंदोलिया भी उपस्थित थे।

रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा घोषित पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत देश भर के करीब चार करोड़ अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी जिसका उपयोग ट्यूशन फीस चुकाने से लेकर रहन-सहन और टाइपिंग आदि पर होने वाले खर्च के लिए किया जा सकेगा। उन्होंने इस योजना की प्रशंसा करते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार से सात सवाल पूछे।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि डॉ अम्बेडकर फेलोशिप योजना के तहत केजरीवाल सरकार ने अनुसूचित जाति के 100 छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष पीएचडी, मास्टर डिग्री आदि के लिए विदेश भेजने की घोषणा की थी। ऐसे में वह बताएं कि अब तक कितने छात्रों को विदेश भेजा गया। इसी प्रकार जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत अब तक कितने छात्रों को आईएएस व आईपीएस बनाने की कोचिंग दी गई और इनमें से कितनों को ढाई हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी गई। इसी प्रकार सीबीएसई परीक्षा देने वाले कितने छात्रों की फीस भरी गई, 80 प्रतिशत अंक लाने वाले कितने अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को लैपटॉप व टेबलेट दिये गए और कितने छात्रों को अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने केजरीवाल सरकार से यह भी जानना चाहा कि उसकी स्नातक कोर्स फीस माफी योजना के तहत कितने छात्रों की फीस माफ की गई इसकी जानकारी उनको देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि केजरीवाल सरकार की शिक्षा व्यवस्था इतनी ही मजबूत है, तो 10वीं कक्षा में ड्राप आउट छात्रों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है?

गुरुवार से भाजपा चलाएगी हस्ताक्षर अभियान

नई दिल्ली,एजेंसी। उत्तरी, पूर्वी औ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का बकाया 13000 करोड़ रुपए की मांग के लिए भाजपा तीन दिनों तक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इस अभियान में 13750 बूथों के कार्यकर्ता 13000 करोड़ रुपए से संबंधित पत्रक वितरित करेगी। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दिल्ली भाजपा महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि नगर निगम का बकाया 13000 करोड़ रुपए की मांग के लिए 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक प्रदेश भाजपा के सभी मोर्चे 1000 प्रमुख स्थानों पर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और जन-जन तक निगम के बकाए की जानकारी पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि 9 जनवरी को सभी पार्कों में मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा 13000 करोड़ रुपए संबंधित पत्रक का वितरण किया जाएगा।

हनुमान मंदिर पुर्नविस्थापित नहीं हुआ तो कोर्ट जाएगी कांग्रेस

- अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर शराब के ठेका खोलने से दिल्लीवासियों के विश्वास को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है

नई दिल्ली,एजेंसी। चांदनी चौक में ऐतिहासिक हनुमान मंदिर अगर पुर्नविस्थापित नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़क से लेकर कोर्ट तक का रूख करेगी। इसी कड़ी में प्रदेश इकाई ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्लीवासियों की ओर से धार्मिक आस्था को देखते हुए चांदनी चौक में ऐतिहासिक हनुमान मंदिर को पुर्नविस्थापित करने और अक्षरधाम मंदिर मेट्रो स्टेशन पर खोली गई शराब की दुकान को एक सप्ताह बंद करे अन्यथा कांग्रेस सड़क पर उतरक कोर्ट तक जाने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि चांदनी चौक स्थित हनुमान मंदिर को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी की अरविन्द केजरीवाल सरकार और भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम पूर्ण रूप से जिम्मेदार है क्योंकि दिल्ली सरकार ने मंदिर को अतिक्रमण बताकर उसे हटाए जाने के लिए भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखा था और भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों सरकारों ने कोर्ट में मंदिर को अतिक्रमण के रुप स्वीकार किया था। ऐतिहासिक चॉदनी चौक में मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ चॉदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल और जिला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। महिला प्रदेश अध्यक्ष अमृता धवन, जय किशन, मनोज गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, अशोक त्यागी, चांद कुमार सैंकड़ो कांग्रेस कार्यकताओं के साथ मौजूद थे।

चौ. अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस दिल्ली की अरविन्द सरकार द्वारा प्रत्येक वार्ड में 3 शराब के ठेके खोलने के निर्णय की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल ने अक्षरधाम मंदिर में दीपावली की पूजा करके दिल्लीवासियों को जो धार्मिक सौहार्द का संदेश देना चाहते थे, दिल्ली सरकार द्वारा अक्षरधाम मंदिर भगवान नारायण के दरवाजे के सामने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर शराब के ठेका खोलने से दिल्लीवासियों के विश्वास को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। चौ. अनिल कुमार ने चेतावनी दी कि यदि अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर शराब की दुकान तुरंत बंद नहीं की तो कांग्रेस कार्यकर्ता इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे।

कोरोना से युद्ध में ड्यूटी पर हुई मृत्यु के आश्रितों को स्थायी नौकरी देगा निगम

- घरों से कूड़े का निष्पादन, कोविड-19 के कारण मृत्यु पर नागरिकों की अंत्येष्टि एंव राशन वितरण का कार्य किया था।

नई दिल्ली,एजेंसी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान हुई मौत पर अब उनके आश्रितों को स्थायी नौकरी दी जाएगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इस बाबत कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कोई भी कर्मचारी (नियमित अथवा अनुबन्ध) यदि कोरोना से युद्ध मे कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया था तो उसके आश्रित को निगम नौकरी देगा। उन्होंने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स ने कोरोना महामारी के दौरान आगे बढ़ कर स्वास्थ्य, सफाई, क्वारंटाईन घरों से कूड़े का निष्पादन, कोविड-19 के कारण मृत्यु पर नागरिकों की अंत्येष्टि एंव राशन वितरण का कार्य किया था। इसमें ए व बी श्रेणी के नियमित/अनुबंध पर कार्यरत अधिकारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को अनुबंध आधार पर) ए व बी श्रेणी में समकक्ष पद पर या सी श्रेणी के प्रवेश स्तर पर नियमित आधार पर योग्याता के अनुसार उपयुक्त पद पर नौकरी दी जाएगी।

उत्तरी दिल्ली के महापौर ने कर्मचारियों से हड़ताल पर न जाने की अपील

नई दिल्ली,एजेंसी। उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के संगठन के साथ बैठक कर उन्हें हड़ताल पर न जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि फंड की उपलब्धता के अनुसार सभी निगम कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। निगम इस ओर सभी प्रयास कर रहा है ताकि निगम कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन दिया जा सके। महापौरकहा कि दिल्ली सरकार निगमों का बकाया फंड नहीं दे रही है जिसके कारण निगम वित्तीय संकट की स्थिति से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि गत दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर 13 दिनों तक धरना दिया था ताकि निगमों को उनका संवैधानिक हक मिल सके। उन्होंने कहा कि हम निगम कर्मचारियों की संवेदना को समझते हैं और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

स्कूलों को जल्दी कैसे खोला जाए, इस पर कर रहे हैं विचार : सिसोदिया

नई दिल्ली, एजेंसी। कोविड-19 के स्कूल खोलने और पढ़ाने के तरीके पहले के जैसे ही नहीं रह सकते। टीकाकरण की तैयारियों की तरह हमें कोरोना पश्चात काल में स्कूल खोलने की भी योजना बनानी होगी। यह कहना है दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का। बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार स्कूली शिक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है।

आगामी 11 से 17 जनवरी, 2021 तक दिल्ली शिक्षा सम्मेलन 2021 होगा। उन्होंने कहा कि हम स्कूलों को फिर से खोलने दौरान बच्चों के शैक्षणिक नुकसान की हर संभव भरपाई पर विचार मंथन करना होगा, जो हम इस सम्मेलन के माध्यम से कर रहे हैं। कोरोना के प्रभाव के साथ ही नई शिक्षा नीति के आलोक में शैक्षणिक रणनीति पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी।

उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में शिक्षा के सर्वोत्तम प्रयोगों से सीखने के साथ ही देश के अन्य स्तकेहोल्डर्स के साथ सहयोग की संभावनाओं का पता भी लगाना है। दिल्ली की शिक्षा-क्रांति के पांच साल के अनुभवों को भी वैश्विक आलोक में देखते हुए आगे की रणनीति बनाने का लक्ष्य है। इस सम्मेलन को दुनिया के जाने-माने शिक्षा विशेषज्ञ संबोधित करेंगे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने सम्मेलन की वेबसाइट भी लांच की और बताया कि सम्मेलन में भारत तथा छह अन्य देशों के 22 शिक्षा विशेषज्ञ स्कूली शिक्षा के विभिन्न विषयों पर विचार रखेंगे। इनमें भारत, फिनलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, सिंगापुर, नीदरलैंड और कनाडा के विशेषज्ञ शामिल होंगे। सम्मेलन 11 जनवरी को शुरू होगा। इसमें बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा विगत पांच साल में दिल्ली के शिक्षा सुधारों पर स्वतंत्र स्टडी की रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। इसके बाद लूसी क्रेहान का की-नोट लेक्चर होगा। उन्होंने पांच देशों की शिक्षा प्रणाली का गहन अध्ययन करके 'क्लेवर लैंड्स' नामक चर्चित पुस्तक लिखी है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 12 से 16 जनवरी 2021 तक प्रतिदिन दो घंटे का ऑनलाइन पैनल डिस्कसन होगा।

इसमें भारत तथा अन्य छह देशों के विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। इसमें शैक्षणिक पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा प्रशासन के साथ ही शिक्षा की बुनियाद, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास, स्कूल प्रबंधन और शिक्षा संबंधी अन्य विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही, नई शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारों की सिफारिश की है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें कोविड-19 के बाद के दौर में स्कूली शिक्षा में जरूरी सुधार पर गहन विचार करना होगा।

सम्मेलन के 22 विशेषज्ञों में प्रो. लैंट प्रिटचेट (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के पूर्व प्राध्यापक, अब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय), डॉ. सेबेस्टियन सुगेट (जर्मनी की रिगेन्सबर्ग यूनिवर्सिटी में शिक्षा विभाग की सीनियर लेक्चरर) के नाम प्रमुख हैं। इसी तरह, डॉ विमला रामचंद्रन (प्रसिद्ध शिक्षाविद), डॉ रुक्मिणी बनर्जी (सीईओ, प्रथम), यामिनी अय्यर (सीईओ, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च), प्रो. विनीता कौल (बाल शिक्षा की विशेषज्ञ) जैसे विद्वान अलग-अलग पैनल में बोलेंगे। सम्मेलन का समापन 17 जनवरी को होगा जिसमें सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए व्यापक साझेदारी के निर्माण की भावी रणनीति पर चर्चा होगी।

दिल्ली में कोरोना के 654 नए मामले, 719 मरीज हुए स्वस्थ

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बुधवार को राजधानी में कोरोना के 654 नए मामले सामने आए। जबकि 719 मरीज स्वस्थ हुए। दिल्ली में कोरोना के अब कुल छह लाख 28 हजार 352 मामले हो सामने आ चुके हैं जिनमें 6 लाख 13 हजार 246 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत भी हो गई। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक कुल दस हजार 625 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं।

21 से 23 दिसंबर दिल्ली में एक हजार से कम कोरोना के मामले सामने आए थे। 21 दिसंबर को 803, 22 दिसंबर को 939 और 23 दिसंबर को 871 मामले सामने आए। हालांकि, 24 दिसंबर को 1,063 मामले दर्ज किए गए, 25 दिसंबर को फिर से 758 और 26 दिसंबर को 655 दर्ज किए गए। 27 दिसंबर को 757 मामले दर्ज किए गए, जबकि 28 दिसंबर को दैनिक मामलों की गिनती 564 थी, जो पिछले पांच महीनों में सबसे कम थी। 29 और 30 दिसंबर को शहर में क्रमशः 703 और 677 मामले दर्ज किए गए। 31 दिसंबर को, 574 मामले दर्ज किए गए और 1 जनवरी को 585 और 2 जनवरी को 494 और 3 जनवरी को 424 और 4 जनवरी को 384 मामले दर्ज किए गए।

जांच बढ़ने से काबू आया संक्रमण : कोरोना का संक्रमण शुरू होने के बाद से ही दिल्ली में औसतन जांच

अधिक होती रही हैं। नवंबर में संक्रमण बढ़ने पर प्रतिदिन 60 हजार सैंपल की जांच होने लगी। बाद में यह संख्या भी बढ़कर 90 हजार के करीब पहुंच गई। इसके तहत आरटीपीसीआर जांच भी बढ़ाई गई। इसके बाद कोरोना की संक्रमण दर में काफी कमी आई।

एक और मरीज में नए स्ट्रेन की पुष्टि, संख्या हुई आठ : राजधानी में कोरोना के नए रूप (स्ट्रेन) से संक्रमित होने वाले एक और मरीज की पुष्टि हुई है। इससे राजधानी में नए स्ट्रेन के मरीजों की कुल संख्या आठ हो गई है। मंगलवार को आठ लोगों की रिपोर्ट आई, जिनमें से एक मरीज में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। वहीं, सात मरीजों की जीनोम सिक्वेंसिंग रिपोर्ट नेगेटिव आई।

किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए मुझे पक्षकार बनाया जाए : नौहटिया

- नौहटिया का कहना है कि दरसल केन्द्र सरकार और किसानों के बीच कोई सही पक्षकार नही है।

नई दिल्ली,एजेंसी। किसान आंदोलन को खत्म करने और किसानों की समस्याओं को निपटाने के लिए मुझे केन्द्र सरकार की ओर से पक्षकार बनाया जाए यह बातें अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बमबम महाराज नौहटिया ने बातचीत के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को 41 दिन लगभग हो गए हैं लेकिन अभी तक यह आंदोलन खत्म नही हुआ बल्कि और तेज होता जा रहा है। नौहटिया का कहना है कि दरसल केन्द्र सरकार और किसानों के बीच कोई सही पक्षकार नही है। इसलिए यह आंदोलन खत्म नही हो पा रहा है और दिन.प्रतिदिन बढता जा रहा है। उनका कहना है कि यदि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और केन्द्रीय कृषि मंत्री हमें सरकार की ओर से पक्षकार बनाएं तो किसानों के साथ सकारात्मक बातचीत कर यह आंदोलन समाप्त कर सकता हूं। इसके लिए केन्द्र सरकार को हमसे संपर्क करने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की वजह से देश विरोधी शक्तियों भी उनके साथ हैं जो अपने आप को किसान होने का दावा कर रहीं है। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को भी बेनकाब कर सकता हूं जो किसानों की आड में देश विरोधी गतिविधियो में लिप्त हैं और मौका फायदा उठाकार खालिस्तान की मांग करने में जुटे हैं।

दो दिन बाद फिर खराब हुई दिल्ली की हवा

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजधानी को प्रदूषण से मिली राहत सिर्फ दो दिन ही टिक सकी। बुधवार के दिन दिल्ली की हवा एक बार फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्र द्वारा संचालित संस्था सफर का अनुमान है कि अगले दो दिन में वायु गुणवत्ता और खराब होगी।

राजधानी दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में बीते चार दिनों से रुक-रुककर बरसात हो रही है। इसके चलते लंबे वक्त के बाद सोमवार और मंगलवार को दिल्ली की हवा अपेक्षाकृत साफ-सुथरी हो गई थी। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक सोमवार के दिन 151 और मंगलवार के दिन 140 के अंक पर रहा था। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। इन दो दिनों के बाद अब हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा में तेजी से इजाफा हो रहा है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार के दिन दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 226 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है।

पंजाब में तीनों कृषि कानून लागू कर कांग्रेस ने की किसानों के साथ गद्दारी : आप

नई दिल्ली,एजेंसी। तीन कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने कांग्रेस पर किसानों के समर्थन में ढोंग करने का आरोप लगाया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा कि कांग्रेस शासित पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने राज्य में तीनों कृषि कानून लागू करके किसानों के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की है। पंजाब के मंत्री भारत भूषण आशु ने कबूला है कि पंजाब में तीनों कानून लागू कर दिए गए हैं, उसी के अनुसार फसलों की खरीद-बिक्री हो रही है और अब राज्य में एमएसपी नहीं रह गई है। चड्ढा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर ने विधानसभा के विशेष सत्र में तीनों काले कानूनों को पंजाब में नहीं लागू होने देने का दावा

किया था, उन्होंने यह झूठ बोला था। अपनी शहादत देने वाले किसानों की आत्मा और उनके परिजन कैप्टन सिंह से पूछ रहे हैं कि तीनों काले कानून क्यो लागू किया? आप प्रवक्ता ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर पुत्र मोह में तीनों कानूनों को लागू करके पंजाब की जनता के हित को भाजपा को बेच दिया है। इस गद्दारी के लिए पंजाब की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफे की मांग करती है। राघव चड्ढा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और कैप्टन द्वारा लगातार कृषि विरोधी तीनों कानूनों का विरोध किया गया। राहुल गांधी इसको लेकर लगातार ट्वीट करते हैं।

कांग्रेस के नेता इस पर लगातार प्रेस कांफ्रेंस करते हैं। पंजाब से कांग्रेस के कुछ सांसद झूठे तरीके से रोजाना 10-15 मिनट के लिए जंतर-मंतर पर बैठ जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से इन काले कानूनों को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं। मीडिया को बाइट दी जा रही है, बयान जारी किए जा रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम इन तीनों काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के बाहर का कोई भी किसान अब पंजाब में आकर अपनी फसल बेच सकता है। अब एमएसपी और मंडी नाम की कोई चीज प्रदेश में नहीं बची है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी गद्दारी, देश के लोगों, पंजाब की मिट्टी और किसानों के साथ नहीं हो सकती। कैप्टन अमरिंदर सिंह वो मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने पिछले कई महीनों से खुलकर इस किसान विरोधी बिल का विरोध करना शुरू किया था। उन्होंने पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कहा था कि मैंने इन तीनों काले कानूनों को पंजाब में लागू होने से रोक दिया है। अब यह तीनों कानून मेरे प्रदेश में लागू नहीं हो सकेंगे, लेकिन उन्होंने प्रदेश के लोगों से झूठ बोला, झूठे आंसू बहाए और कैमरे के सामने पत्रकारों से भी झूठ कहा। सच यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह तीनों काले कानून पंजाब में लागू कर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम लगातार बताते आ रहे थे कि जुलाई और अगस्त 2019 में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इन तीनों काले कानूनों का ड्राफ्ट बनाया गया था। उस मीटिंग में कैप्टन साहब भी मौजूद थे। जब से आंदोलन शुरू हुआ है, पंजाब के मुख्यमंत्री एक बार भी प्रदेश के किसानों से मिलने के लिए नहीं गए। पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, लेकिन 10-15 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर बैठे किसानों से मिलने के लिए नहीं जाते हैं। अपने बेटे के मोह में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के किसानों के हित भाजपा को बेच दिए हैं।

संपादकीय

सियासत में पीछा करते तीखे सवाल

बीतता दशक बड़े राजनीतिक बदलावों का दशक रहा है। 1989 से 2014 तक 25 साल का एक सिलसिला था, जब मिली-जुली सरकारों ने शासन किया। वह एक तरह से अल्पमत की ही सरकारें थीं। बीतते दशक में ऐसा लग रहा है कि हम फिर एकदलीय सरकार के युग में वापस चले आए हैं। विगत दशकों में कई दिग्गज प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन यह कहना होगा कि इंदिरा गांधी के बाद पहली बार इस तरह के एक अभ्यस्त राजनेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्हें इसी दशक में लगातार दो बार बहुमत मिला है। अखिल भारतीय स्तर पर उन्हें एक जननेता माना जा सकता है, जिनका राजनीति और प्रशासन पर मजबूत प्रभाव है। एकदलीय सरकार की वापसी और एक दिग्गज नेता का उत्थान इस दशक के दो बड़े बदलाव हैं। बेशक, साल 2014 के बाद सियासी हालात बहुत बदले हैं। इस दशक के खत्म होते-होते राजनीति भी निशाने पर आई है। स्पष्ट है, पहले जो आर्थिक विकास दर था, उसमें कमी आई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जिस तरह से लोगों को पहले ऋण मिलते थे, अब नहीं मिल रहे। बैंक भी ऋण वसूली पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक अनेक छोटे-बड़े उद्योगों की हालत खस्ता है। यह ध्यान रखना चाहिए, आर्थिक संकट जब आता है, तब बड़े उद्योग समूह ज्यादा ताकतवर होकर उभरते हैं। उनके पास संसाधन होते हैं, मुश्किल हालात में भी वे व्यापार करने में सक्षम होते हैं। उदारीकरण का जो दौर 1991 से चल रहा है, उसमें चार-पांच उद्योग समूह हैं, जिनका बहुत फैलाव हुआ है। कई लोगों का कहना है, अभी भारत में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं, अमेरिका में उसी तरह के बदलाव 1900 और 1910 के बीच हुए थे। तब वहां तीन-चार बड़ी कंपनियों का वर्चस्व बन गया था, जैसे स्टैंडर्ड ऑयल का। वहां बहुत प्रतिरोध हुआ था और सरकार ने एंटी ट्रस्ट लॉ बनाकर उन बड़ी कंपनियों को तुड़वाया था। भारत में भी आज चर्चा हो रही है, लेकिन वैसे हालात क्या यहां आगामी दशक में बनेंगे? हम नहीं जानते। वैसे पंडित नेहरू के समय में भी वामपंथी कहते थे कि टाटा-बिड़ला पल रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कई बार कहा। हालांकि, आज हालात उससे बहुत अलग हैं। समय के साथ राजनीति पर पूंजी व व्यापार का प्रभाव बढ़ा है। आज राजनीति या कूटनीति से परे जाकर तमाम देश व्यापारिक हितों के लिए गठजोड़ बना रहे हैं। पूंजी का प्रवाह बढ़ा है। फिर भी हमें गौर करना चाहिए कि हमारे यहां ज्यादा विदेशी पूंजी शेयर बाजार में आई है। भारत में विदेशी पूंजी का आना पहले से तो बहुत बढ़ा, लेकिन उस तरह का नहीं है, जैसा चीन, मलेशिया और ताईवान में है। दूसरा, विकसित अमेरिका, जापान, यूरोपीय देशों से निर्यात का जो सिलसिला था, वह थम रहा है। संरक्षणवाद की लहर हर देश में चल रही है, जिससे वैश्वीकरण इस दशक में कुछ हद तक कमजोर पड़ा है। जब निर्यात के मोर्चे पर भारत की मुश्किलें बीतते दशक में तेजी से बढ़ी हैं, जब हम अपने उत्पादन के लिए भी विदेशी आयात पर निर्भर हो रहे हैं, तब यहां के विकास को खतम होने से कैसे बचाया जाएगा? यह सवाल आगामी दशक में भी पीछा करेगा। भारत में विकास का सवाल आसान नहीं है। भारत और बाकी लोकतंत्रों में बड़ा फर्क है। यहां अनेक प्रांतों, भाषाओं, धाराओं को एक सूत्र में पिरोना मुश्किल है। अभी भी 45 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं, ऐसी स्थिति अन्य किसी देश में नहीं है। दूसरी बात, कई ऐसे देश हैं, जहां औद्योगिकीकरण तब हुआ, जब वहां लोगों के पास मत डालने का हक नहीं था। भारत में विकास की राजनीति इसलिए भी ज्यादा मुश्किल नजर आती है, क्योंकि सबकी आकांक्षाओं, रंगों, आकारों को एक नीति में ढालना कठिन है। किसान, मध्यवर्ग, श्रम संगठन सभी बहस में हुए हैं। ये लोग सवाल उठाएंगे और यहां बड़े उद्योगों पर दबाव बना रहेगा। बड़े कॉरपोरेट का राजसत्ता से कैसा नाता रहेगा, क्या हमारे बड़े नेता उनसे काबू में रहेंगे? क्या पारदर्शिता रहेगी ऐसी चिंताएं, बीतते दशक में लगातार बनी रही हैं और आगे भी बनी रहेंगी। जाति, धर्म इत्यादि का प्रभाव भी इस दशक में राजनीति में बढ़ा है। पहले मिली-जुली संस्कृति का दबाव था, पर पिछले छह-आठ वर्षों में परिवर्तन हुआ है। हिंदुत्व व हिंदू राष्ट्र की चर्चा बढ़ी है। अब करीब 35 से 40 प्रतिशत वोट वाली भाजपा ने 30 साल पहले जो सवाल खड़े किए थे, राममंदिर, अनुच्छेद 370, गाय इत्यादि, वे हल हो चुके हैं। अब हमारी राजनीति का व्याकरण बदल गया है, लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव है कि विरोधी दल, खासकर कांग्रेस भी विरोध नहीं कर रही है। आगामी दशक में शायद ऐसी ही राजनीति जारी रहेगी। संस्थान, संगठन, सांस्कृतिक जगत, शिक्षा इत्यादि में काफी कुछ होना बाकी है। वैसे भी भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इशारा कर चुके हैं कि हम दिल्ली राज करने ही नहीं, समाज बदलने आए हैं। देश बदलने के लिए कांग्रेस ने लंबा रास्ता तय किया था और भाजपा भी वैसी ही राह पर दिखने लगी है।

बेशक, बीतते दशक में राजनीति में सोशल मीडिया की भूमिका बहुत बढ़ी है। सोशल मीडिया चलाने वाली कुछ कंपनियां इतनी मजबूत हो गई हैं कि सवाल उठने लगे हैं। क्या बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां भी राजनीति की दिशा तय करेंगी? गूगल, फेसबुक इत्यादि पर इसी दशक में मुकदमे शुरू हो चुके हैं। लिंगभेद, पर्यावरण जागरूकता लाने में सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है, युवा पीढ़ी इसी के जरिए जागी है। बीतते दशक में आम आदमी की भूमिका बढ़ी है। उसका आक्रोश अद्भुत स्वरूपों में सामने आ रहा है। जैसे ट्रंप, बोरिस जॉनसन जैसे नेताओं का उत्थान, बहुतों ने नहीं सोचा था कि ऐसे नेता भी उभरकर आएंगे। चुनावों में कई बार अनपेक्षित नतीजे आ रहे हैं। भारत में ही अगर लें, तो नरेंद्र मोदी 21 साल पहले पार्टी दफ्तर में रहते थे। वह उभरकर सामने आए। शायद यह सागर मंथन जैसा दौर है। राजनीतिक दलों में बड़े परिवर्तन हुए हैं। इस दशक में राजनीतिक दलों, संगठनों से परे भी स्वतंत्र आवाजों का उत्थान हुआ है। मलाला एक मिसाल है और 16 साल की वह ग्रेटा थनबर्ग भी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र आमसभा में तल्खी के साथ यह सवाल उठा दिया कि आपने हमारे लिए दुनिया में क्या बचाकर रखा है? बड़े लोग भी झुके, ग्रेटा की सुनवाई हुई।

प्रवीण कुमार सिंह

नवाचारों से ही निकलेगा कृषि संकट का समाधान, किसानों की आय बढ़ाने के अभिनव प्रयोग

कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण सुधारों की कड़ी में कृषि परिषद का गठन बाकी रह गया है। इसे जीएसटी परिषद की तरह ही राज्य के प्रतिनिधियों के सहयोग से चलाया जाना चाहिए। उम्मीद की जा सकती है कि ऐसी संस्थाएं, कृषि क्षेत्र में बेहतर समन्वय और एकरूपता ला सकेंगी। कृषि संबद्ध क्षेत्रों जिसमें अंडे व मांस समेत मत्स्य उत्पादन जैसी चीजें शामिल हैं, इनके भंडारण, संरक्षण और मार्केटिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सरकार इसके लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन जैसी योजना तो चला रही है, लेकिन इस क्षेत्र में संभावनाएं और भी ज्यादा हैं।

सितंबर में केंद्र सरकार ने तीन नए कृषि कानून बनाए, जिसके बाद से ये निरंतर चर्चा में हैं। इन नए कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलनरत हैं। दरअसल किसानों को इस बात की आंशका है कि मुक्त बाजार की अवधारणा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को कमजोर कर सकती है और किसानों को बाजार की शक्तियों के प्रति संवेदनशील बना सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए आश्वासन दिया है कि इन कानूनों से एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एमएसपी जैसे पहले दी जाती थी, वैसे ही दी जाती रहेगी, इसे समाप्त नहीं किया जाएगा।

सरकार द्वारा सुधारवादी कदम उठाए जाने के बावजूद किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के कारण कई महत्वपूर्ण सवाल उभरते हैं कि विरोध के स्वर के बीच कृषि क्षेत्र को आखिर लाभकारी और प्रतिस्पर्धी कैसे बनाया जाए? कृषि को आधुनिक कैसे बनाया जाए? टेक्नोलॉजी युक्त कैसे बनाया जाए? आधुनिक अविष्कारों को खेतों तक कैसे पहुंचाया जाए? इन सवालों का जवाब तलाशना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि आजादी के सात दशक बीत जाने के बावजूद भारत के राजनीतिक परिदृश्य में कृषि क्षेत्र की समस्याओं का कोई दीर्घकालीन समाधान नहीं ढूंढा जा सका है, जिसकी वजह से देश में लंबे अरसे से कृषि संकट चला आ रहा है।

हमारे देश में खेती-किसानी का प्राथमिक संकट संकुचित होते खेतों के आकार में दिखाई देता है। खेतों का औसत क्षेत्र निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। वर्ष 2011 की कृषि जनगणना के अनुसार, वर्ष 1970-71 के दौरान जहां एक किसान के

पास औसतन 2.28 हेक्टेयर खेत हुआ करता था, वह सिमटकर 1.08 हेक्टेयर ही रह गया है। भारत में खेती-बाड़ी में लगी जनसंख्या में से अधिकांश छोटी जोत के किसान हैं। ये कुल कृषि भूमि का केवल 44 प्रतिशत ही जोतते हैं और कुल कृषि आउटपुट में इनका लगभग 50 प्रतिशत का योगदान है। भू-जोतों का आकार छोटा और आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद नहीं होने से किसानों को इससे इतनी आय प्राप्त नहीं हो पाती है कि वह कृषि में भावी निवेश कर सके। जोतों का छोटा आकार एवं विखंडित स्वरूप होने के कारण इनमें आधुनिक कृषि मशीनों का इस्तेमाल कठिन हो जाता है। कृषि में यंत्रीकरण यानी मशीनीकरण का स्तर कम होने से कृषि उत्पादकता में कमी होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में कृषि का मशीनीकरण लगभग 40 प्रतिशत है, जो कि ब्राजील के 75 प्रतिशत तथा अमेरिका के 95 प्रतिशत से काफी कम है। कृषि गतिविधियों में तेजी प्रदान करने और कृषि को बागवानी से जोड़ने तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि के यंत्रीकरण से किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है।

कर्जदारी निर्वाह कृषि की सर्वव्यापी विशेषता है, परंतु भारत में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक दुखदायी है। एक अनुमान के मुताबिक, भारतीय किसान की प्रति व्यक्ति मासिक आय औसतन लगभग तीन हजार रुपये (कृषि एवं पशुपालन को जोड़कर लगभग छह हजार रुपये) है और देश के लगभग 70 प्रतिशत किसान कर्ज में डूबे हैं। इसमें बड़ी चिंता की बात यह है कि बहुत सारे किसानों ने गैर संस्थागत स्नोतों जैसे महाजनों आदि से कर्ज ले रखा है। हालांकि सरकारी-सहकारी समितियों से किसानों को कम ब्याज पर ऋण की सुविधा दी जा रही है, परंतु इसका प्रभाव मझोले और बड़े किसानों तक ही सीमित है। बड़ी संख्या में छोटे किसान अभी भी व्यावसायिक ऋणदाताओं से भारी ब्याज दर पर कर्ज लेते हैं। महाजन का कर्ज न चुकाने की स्थिति में किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध के बीच आज इस समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं है।

वर्तमान में कृषि क्षेत्र में कॉलेटरल फ्री लोन की सीमा 1.6 लाख रुपये है, जबकि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों और शिक्षा के लिए ऐसे ही ऋण की सीमा क्रमशः 10 लाख एवं साढ़े सात लाख रुपये है। ऐसे में आने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर तीन लाख कर देना चाहिए, क्योंकि सीमांत और छोटे किसानों द्वारा नवाचार अपनाने की दिशा में सामयिक संस्थागत ऋण मुख्य भूमिका निभाते हैं, अतः इस संदर्भ में विशेष रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

विपणन यानी मार्केटिंग सुविधाओं के अभाव में किसानों को अपने खेत की उपज को बेचने के लिए स्थानीय व्यापारियों और मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें फसल का सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेलवमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2000 से 2017 के बीच कृषि उत्पादों की कम कीमत मिलने से किसानों को करीब 45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। किसानों को उनकी फसलों की कम कीमत मिलने की बड़ी वजह कृषि मंडियों या कृषि उत्पादों के बाजारों की अपर्याप्त संख्या का होना भी है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए गठित एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, हर पांच किमी पर एक मंडी होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में यह दूर की कौड़ी है। कृषि क्षेत्र हमारे देश के लगभग 15 करोड़ किसान परिवारों की आजीविका को सीधे-सीधे प्रभावित करता है। ऐसे में यह और भी जरूरी हो जाता है कि इस क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के व्यावहारिक प्रयास तेज किए जाएं। दरअसल कृषि क्षेत्र को साल 1991 में किए गए आर्थिक सुधारों की तरह व्यापक सुधारों की जरूरत है। इसमें केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। साथ ही, इसके लिए बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक को भी इसमें शामिल किया जाना जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कृषि भारत की एक राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन भारत के विभिन्न हिस्सों में कृषि संबंधी समस्याओं का प्रकार अलग-अलग है, अतः राष्ट्रीय नीति के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं को ध्यान में रखकर कदम उठाए जाने चाहिए। कृषि उत्पादों के भंडारण और उनके वितरण वाले पहलू पर सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे यहां उत्पादन पर्याप्त मात्र में होने के बावजूद एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो खाद्यान्न के अभाव से जूझ रहा है। हालांकि सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसे उपाय जरूर किए हैं, लेकिन अभी यह उपाय नाकाफी हैं।

कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण सुधारों की कड़ी में कृषि परिषद का गठन बाकी रह गया है। इसे जीएसटी परिषद की तरह ही राज्य के प्रतिनिधियों के सहयोग से चलाया जाना चाहिए। उम्मीद की जा सकती है कि ऐसी संस्थाएं, कृषि क्षेत्र में बेहतर समन्वय और एकरूपता ला सकेंगी। कृषि संबद्ध क्षेत्रों जिसमें अंडे व मांस समेत मत्स्य उत्पादन जैसी चीजें शामिल हैं, इनके भंडारण, संरक्षण और मार्केटिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सरकार इसके लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन जैसी योजना तो चला रही है, लेकिन इस क्षेत्र में संभावनाएं और भी ज्यादा हैं।

साख का सवाल

देश में कोरोना से बचाने वाले टीकों- कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमर्जेंसी इस्तेमाल की इजाजत देशवासियों के लिए जितनी बड़ी राहत की खबर बन सकती थी, उतनी नहीं बन पाई। वजह यह रही कि खबर आने के ठीक बाद विपक्ष के कई नेताओं ने इस मंजूरी पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि मंजूरी देने में जो हड़बड़ी दिखाई गई है, वह बेहद खतरनाक है। सरकार और सत्तारूढ़ दल की तरफ से इन आरोपों का जवाब चिर-परिचित अंदाज में विपक्षी नेताओं पर हमले की शक्ल में दिया गया। निश्चित रूप से विपक्ष के कुछ नेता अवसर की अपेक्षा के अनुरूप गंभीरता नहीं दिखा सके।

इन वैक्सीनों को बीजेपी का टीका करार देना और इन्हें नपुंसकता से जोड़ना न केवल गलत है बल्कि कठिन चुनौती के इस दौर में देशवासियों के बीच अविश्वास और संदेह का माहौल पैदा करता है। बावजूद इसके, विपक्षी नेताओं के उठाए सवालों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। यह सच है कि किसी लोकतांत्रिक देश में राजनेताओं के बयानों की पहुंच ज्यादा होती है और इस वजह से इन बयानों की गूंज ज्यादा बड़ी हो गई है लेकिन सवाल सिर्फ राजनीतिक हलकों में नहीं, विशेषज्ञों और जानकारों की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत बायोटेक द्वारा बनाए गए टीके कोवैक्सीन का फेज-3 ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है।

ऐसे में यह सवाल तो बनता है कि डीसीजीआई (ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया) ने आखिर किस आधार पर इस वैक्सीन को सुरक्षित मान लिया। मंजूरी की घोषणा के बाद स्वाभाविक ही अपेक्षा की जा रही थी कि इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन लिखित वक्तव्य पढ़ने के बाद बिना कोई सवाल लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क ने ठीक ही नियामक से अनुरोध किया है कि जिन आंकड़ों के आधार पर मंजूरी देने का फैसला लिया गया है, उन्हें सार्वजनिक किया जाए ताकि उनका स्वतंत्र परीक्षण किया जा सके। देश में टीकों को लेकर हिचक पैदा करने वाली कई घटनाएं हो चुकी हैं जिन पर कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण अबतक नहीं आया है। एक बहुचर्चित मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री टीका लेने के बाद कोरोना संक्रमित हो गए। यह कहना काफी नहीं कि उन्होंने एक ही डोज लिया था, इसलिए संक्रमित हो गए। इसका जांच आधारित स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए कि वह संक्रमण किसी रूप में टीके का ही दुष्परिणाम तो नहीं था। अमेरिका और ब्रिटेन में टीके के नतीजों को लेकर सवाल उठे तो ठहरकर उनके संतोषजनक जवाब दिए गए। कोई कारण नहीं कि भारतीय नियामक संस्थाएं लोगों को आश्वस्त करने की अपनी जवाबदेही से बचने का प्रयास करें। सवाल सिर्फ इस टीके का नहीं, देश के पूरे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की साख का है।

मोटे अनाज गरीबी के प्रतीक माने जाते थे, वे अब बन गए अमीरों की पसंद

इन दिनों किसान आंदोलन की खबरों के बीच खेती-किसानी से जुड़े कुछ अहम मुद्दे पार्श्व में चले गए हैं। अपनी नियति सुधारने में जुटे किसान यदि सरकारी नीतियों के बजाय कुछ पुरानी परंपराओं पर गौर करें तो भी उनका बहुत भला हो सकता है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इन दिनों नकदी फसलों की बातें भी लगातार हो रही हैं। ऐसी फसल के पैसे किसानों को हाथोंहाथ मिल जाते हैं। अभी सर्दी का मौसम है। मक्के-बाजरे की रोटी, मेथी के साग, उड़द की धुली दाल के साथ खाने की यादें आ रही हैं। बाजरा गरम होने के कारण गरमी के दिनों में नहीं खाया जाता। इसी तरह नया गेहूं भी एकदम से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह बहुत गरम होता है। इससे पेट के बहुत-से रोग हो जाते हैं। इसलिए पुराना करके खाना चाहिए। आज इस तरह की बातें संभव है कि गांवों में भी सभी को याद न हों, क्योंकि अनुभवजन्य ज्ञान अक्सर उसी पीढ़ी के साथ समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस ज्ञान को सहेजकर उसका अधिकतम लाभ उठाना समय की मांग है।

यह सही है कि पहले घरों में गेहूं ज्यादा नहीं खाया जाता था। लोग मोटा अनाज ही अधिक खाते थे जिसे बेझर कहते थे। उसमें बाजरा, मक्का, जौ, जई और चना आदि होते थे। ये गेहूं से सस्ते भी होते थे। तब सिंचाई के पर्याप्त साधन न होने के कारण किसान बारिश पर ही निर्भर रहते थे। लिहाजा वे खेतों में मुश्किल से एक या दो फसल ही उगा पाते थे। इसके चलते पिछली सदी के छठे दशक में भारत में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। तब देश में अनाज की भारी कमी हो गई थी। देश के लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए अमेरिका से पीएल-480 के तहत लाल गेहूं आयात किया गया था। हालांकि वह इतना खराब था कि खाया नहीं जाता था। उसकी रोटियां रबर की रोटी जैसी लगती थीं, लेकिन खाने की मजबूरी थी।

तभी सोचा गया था कि हमें देश में ही ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जिससे अपनी आबादी के लिए खाद्यान्न की जरूरतें पूरी हो सकें। इसलिए सिंचाई के साधनों, उर्वरकों, कीटनाशकों और नई किस्म के बीजों के जरिये इंदिरा गांधी के शासन में हरित क्रांति की परिकल्पना की गई, लेकिन दुख की बात है कि तब हरित क्रांति के जरिये गेहूं और धान की खेती पर ही ज्यादा जोर दिया गया। इसलिए किसान मोटे अनाज को छोड़कर गेहूं और धान उगाने लगे। फिर गेहूं खाना हैसियत का प्रतीक माना जाने लगा और मोटे अनाज खाने वालों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि गेहूं और धान उन दिनों की नकदी फसलें थीं, जबकि आज किसान कह रहे हैं कि गेहूं और धान उगाना उनके लिए कोई खास फायदे का सौदा नहीं रहा।

देखिए वक्त भी कैसे बदलता है। हमारे खाने-पीने की आदतें बदलने से इन दिनों पैसे वाले लोग गेहूं नहीं खाना चाहते। वे मानते हैं कि गेहूं खाने से तमाम रोग होते हैं। गेहूं ग्लूटन एलर्जी (एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी जो आंतों और शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित करती है), मोटापे, डायबिटीज आदि का कारण बनता है। एक समय गेहूं खाने के नुकसान पर लिखी गई एक किताब 'व्हीट बैली' भी बहुत पसंद की गई थी। इसे अमेरिका के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. विलियम डेविस ने 2011 में लिखा था। उनका कहना है कि दुनियाभर में मोटापे के लिए एक ही अन्न जिम्मेदार है-वह है गेहूं। ऐसे में गेहूं बंद करने से न केवल वजन कम होता है, बल्कि बहुत से दूसरे रोगों से भी छुटकारा मिलता है।

हालांकि यह भी कितनी विचित्र बात है कि गेहूं के पौधों से बना रस तमाम उन्हीं रोगों को दूर करने वाला माना जाता है, जिनका कारण गेहूं को बताया जाता है। इन दिनों हर जगह इस तरह के ताजे रस बिकते देखे जा सकता हैं। हालांकि आज कई शोध कह रहे हैं कि गेहूं के मुकाबले मोटे अनाज शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। ये शरीर के पोषण में भी सहायक हैं। इसीलिए इन दिनों मोटे अनाज खासे महंगे बिकते हैं। वे बोरियों में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे पैकेट में बिकते दिखाई देते हैं। ऑर्गेनिक के नाम पर तो उसके मुंहमांगे दामों पर हर जगह खरीदार मौजूद हैं। अपने देश में विदेशों से आयातित मोटे अनाज भी खूब लोकप्रिय हो रहे हैं। एक तरह से आज ये नई नकदी फसल हैं। जिन मोटे अनाजों को एक समय गरीबी का प्रतीक माना जाता था, वे अब हैसियत बताने वाले बन गए हैं। उन्होंने गेहूं की हैसियत को पछाड़ दिया है। आज मेले-ठेलों में एक बाजरे की रोटी डेढ़-दो सौ रुपये की मिल रही है। जिस रोटी को पहले हमारी मां या दादी बिना चकला-बेलन की मदद के ही हाथों में पानी लगाकर बना देती थीं, तब उसकी कीमत हमारी नजरों में कुछ नहीं थी। हम जैसे लोग तो बाजरे, ज्वार या मक्के की रोटी का नाम सुनते ही भागते थे, लेकिन आज यदि उसी तरह की रोटी खाने के लिए लंबी यात्रा तक करने से भी गुरेज नहीं करते। इसके अलावा अब तो गेहूं की पारंपरिक खेती के बजाय लोग फूलों, सोयाबीन, मशरूम और महंगी सब्जियों की खेती भी बड़े पैमाने पर करने लगे हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हाथोंहाथ पैसा मिल जाता है। एक साथ इनकी कई-कई फसलें भी ली जा सकती हैं, लेकिन यदि इन नकदी फसलों को उगाने पर ही हमारा जोर रहा तो हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद देश में खेतों से मेथी, पालक, बथुआ और मूली आदि गायब हो जाएं और हम सब हरी सब्जियों के लिए तरस जाएं, क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा नहीं होती।

लद्दाख में भारतीय सेना ने चीन से भयाक्रांत देशों में जगाया भरोसा, भारत चीनी वार का पलटवार करने में सक्षम

एक ऐसे समय में यह सब चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं जब वह स्वयं को वैश्विक नेतृत्व के दावेदार के तौर पर आगे बढ़ाने में जुटा था। इस साल चीन के प्रति दुनिया में दुर्भावना बढ़ी है और इसी कारण दुनिया चीन पर अपनी निर्भरता घटाने में जुट गई है। परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के समीकरण बदल रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो यह साल वैश्विक विनिर्माण ढांचे के पुनर्गठन का भी साल रहा है और इस मामले में चीन की जमीन खिसक रही है। उसके द्वारा रिक्त किए जा रहे इस स्थान की पूर्ति में भारत जैसे देश बखूबी उभरे हैं।

बीते कुछ दशकों में किसी एक साल ने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को शायद ही इतना प्रभावित किया हो जितना 2020 ने। इस साल की शुरुआत ही चीन के वुहान से निकले उस कोरोना वायरस से हुई जिसने जल्द ही पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया। इसका प्रकोप इतना बढ़ गया कि कोरोना से उपजी कोविड-19 बीमारी को वैश्विक महामारी घोषित करना पड़ा। चूंकि इसका कोई उपचार नहीं था तो उसके संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प था। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों ने ऐसा ही किया। इसकी वजह से सब कुछ थम गया और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। परिणामस्वरूप सेहत पर मंडराए इस संकट ने सामान्य जनजीवन से लेकर रोजगार तक पर घातक प्रहार किया। ऐसे में यह साल इस आपदा से जुड़ी तमाम त्रासद तस्वीरों के लिए भी याद रखा जाएगा।

दुनिया के अधिकांश देशों ने चीन को ही इस आपदा का असल दोषी माना। इसकी वजह भी स्पष्ट है कि नवंबर 2019 में ही चीन में इस जानलेवा वायरस की व्यापक मौजूदगी के बावजूद बीजिंग ने वैश्विक समुदाय को समय से इसकी सूचना ही नहीं दी। इतना ही नहीं जब दुनिया को इसकी भनक लगी तब भी चीन इसे छिपाकर उस पर पर्दा डालने का प्रयास करता रहा। यहां तक कि उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था पर भी अपने प्रभाव से शिकंजा कसा। इसी कारण डब्ल्यूएचओ ने न

केवल कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित करने में विलंब किया, बल्कि उसके लिए चीन को जिम्मेदार मानने से ही इन्कार कर दिया। इस वैश्विक संस्था पर चीन के अंकुश का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि जब इस महामारी की पड़ताल के लिए उसे अपनी जांच टीम चीन भेजनी थी तो यह काम भी उसे बीजिंग की शर्तों पर ही करना पड़ा। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने कोरोना को लेकर जवाबदेही तय करने और व्यापक जांच का मुद्दा उठाया तो चीन ने अपने आर्थिक दबदबे से उलटे उसी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चीन के प्रति नकारात्मक धारणा बनने के साथ वह और मजबूत होती गई।

इतने पर भी चीन नहीं माना। जब पूरी दुनिया उसके यहां से निकले वायरस से जूझने में जुटी थी तो उसने इस आपदा में अपने भौगोलिक विस्तार का अवसर तलाशने का दुस्साहस किया। उसने जापान के सेनकाकू द्वीप से लेकर दक्षिणी चीन सागर में अपने पड़ोसियों को परेशान करना शुरू कर दिया। हालांकि जब उसने हिमालयी क्षेत्र में भारत को चुनौती दी तो भारत ने न केवल उसका कड़ाई से प्रतिकार किया, बल्कि उसने चीन की किसी भी धौंस-धमकी को कोई तवज्जो नहीं दी। दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम रण क्षेत्रों में से एक लद्दाख में भारतीय सेना के शौर्य ने चीनी सैनिकों को करारा और माकूल जवाब दिया। इस तरह भारत ने चीन द्वारा बनाए जा रहे दबाव की हवा निकालकर रख दी। इससे पूरी दुनिया और खासकर चीन से भयाक्रांत देशों में यह भरोसा जगा कि भारत चीनी वार का पलटवार करने में सक्षम है। इसका ही नतीजा रहा कि जिस ऑस्ट्रेलिया को चीन ने धमकाया वह भारत के साथ मिलकर मालाबार युद्ध अभ्यास के लिए आगे आया। इस दौरान भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अमेरिका और जापान को साधकर क्वॉड जैसे उस मंच को मजबूती दी जो भविष्य में चीन की चुनौती को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है।

सामरिक मोर्चे के अलावा कूटनीतिक अखाड़े में भी चीन को मुंह की खानी पड़ी। उदाहरण के तौर पर चीन अब तक जिस 'हद-प्रशांत रणनीति' को खारिज करता आया है उसे इस साल व्यापक मान्यता हासिल हुई। अमेरिका के अलावा यूरोपीय देशों और यहां तक कि आसियान राष्ट्रों द्वारा इस क्षेत्र का महत्व स्वीकारने और उसके अनुरूप नीतियां बनाने से स्पष्ट है कि अब इस अवधारणा को स्वीकृति मिल रही है जो चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं। श्रीलंका में राजपक्षे बंधुओं की सत्ता के बावजूद चीन को वहां उनके पहले कार्यकाल जैसा भाव नहीं मिल रहा। इसके विपरीत श्रीलंका भारत के साथ गलबहियां कर रहा है। मालदीव भी उसी नक्शेकदम पर भारत से प्रगाढ़ता बढ़ा रहा है। यहां तक कि म्यांमार जैसे देश बींजग को आईना दिखा रहे हैं। नेपाल में हालिया राजनीतिक उठापटक में भी चीनी दखल को जिम्मेदार माना जा रहा है जिससे वहां की राजनीतिक बिरादरी में गहरा असंतोष है। और तो और अफगानिस्तान ने चंद रोज पहले हुए जासूसी कांड में चीन से जवाब मांगा है।

आर्थिक मोर्चे पर भी इस साल चीन को खासी तपिश झेलनी पड़ी है। दुनिया के करीब 70 देशों ने अपने यहां 5जी की होड़ से उस हुआवे कंपनी को बाहर कर दिया है जिसे चीन अपने राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में देखता आया है। दुनिया की तमाम कंपनियां चीन से अपनी विनिर्माण इकाइयां ले जा रही हैं। अमेरिका इस मामले में खासा सक्रिय हुआ है। वहीं जापान ने तो चीन छोड़कर जाने वाली अपनी कंपनियों के लिए विशेष पैकेज तक का एलान किया है। भारत भी इससे बन रहे अवसरों को भुनाने में जुट गया है। ऐसे प्रयास रंग लाते भी दिख रहे हैं। बीते दिनों देश में कई उद्योगों विशेषकर स्मार्टफोन निर्माण के लिए कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। उनमें से कुछ संयंत्र तो काम भी करने लगे हैं।

एक ऐसे समय में यह सब चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं जब वह स्वयं को वैश्विक नेतृत्व के दावेदार के तौर पर आगे बढ़ाने में जुटा था। इस साल चीन के प्रति दुनिया में दुर्भावना बढ़ी है और इसी कारण दुनिया चीन पर अपनी निर्भरता घटाने में जुट गई है। परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के समीकरण बदल रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो यह साल वैश्विक विनिर्माण ढांचे के पुनर्गठन का भी साल रहा है और इस मामले में चीन की जमीन खिसक रही है। उसके द्वारा रिक्त किए जा रहे इस स्थान की पूर्ति में भारत जैसे देश बखूबी उभरे हैं। अपने संसाधनों के सापेक्ष भारत ने कोरोना आपदा का कहीं बेहतर तरीके से सामना करके भी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। ऐसे में यदि भारतीय नेतृत्व अपनी नीतियों पर इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा तो चीन का उतार भारत के उभार का पड़ाव बन सकता है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह, टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

एक नजर

राजस्थान की गहलोत सरकार ने मकर सक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे की बिक्री पर लगी रोक

जयपुर । राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मकर सक्रांति (14 जनवरी) के मौके पर पतंगबाजी के लिए बेचे जाने वाले चाइनीज मांझे पर रोक लगा दी है। इस संबंध में राज्य सरकार के गृह विभाग ने जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग के निर्देश के अनुसार चाइनीज मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से तैयार किया जाता है जो पतंग के पेंच लड़ाने में अधिक कारगर होता है। इस कारण इसका प्रयोग अधिक होने लगा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बना हुआ होने के कारण बेहद धारदार और विधुत का सुचालक होता है। इसके उपयोग के दौरान दुपहिया वाहन चालकों और पक्षियों के जान-माल का नुकसान होता है। चाइनीज मांझा वाले धागे जब बिजली के तारों के संपर्क में आते हैं तो विधुत सुचालक होने के कारण यह पतंगबाजी करने वालों के लिए भी जानलेवा साबित होते हैं। बिजली के तार भी इससे कई बार कट जाते हैं। कई बार दो तारों के बीच चाइनीज मांझे के संपर्क से शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। इस कारण सरकार ने इसके थोक व खुदरा बिक्री पर रोक लगाई है। गृह विभाग के निर्देश के बाद विभिन्न जिला कलेक्टरों ने अपने मातहत अधिकारियों को आदेश जारी कर बाजार में इस मांझे की बिक्री रोकने को लेकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में मकर संक्रांति के मौक पर काफी बड़े पैमाने पर पतंगबाजी होती है। इसमें चाइनीज मांझे का उपयोग अधिक होता है। प्रतिवर्ष इसके कारण दुर्घटनाएं भी होती है। कई लोगों की गर्दन कटने की बात भी पिछले सालों में सामने आई है।

कोरोना में पक्षियों पर की महामारी से चिंतित सरकार, आमजन को किया जा रहा सतर्क

जयपुर । राजस्थान में कोरोना महामारी का कहर कम होने के बाद अब बर्ड फ्लू का असर बढ़ा है। प्रदेश में अब तक करीब 1200 पक्षियों की मौत हुई है, जिनमें 750 कौवे हैं। प्रदेश में अब तक करीब 250 मुर्गियों की भी मौत हुई है। बढ़ते बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से लगती सीमा पर सतर्कता बढ़ाने के साथ ही जयपुर में जांच लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। पक्षियों पर आए संकट को देखते हुए पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा व सचिव आरूषि मलिक ने जिला स्तर के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया और बर्ड फ्लू को देखते हुए विशष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कटारिया ने बताया कि भोपाल की तरह जयपुर में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में एवियन एन्फ्लूएंजा से कौओं सहित अन्य पक्षियों की मौत की घटना को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भरतपुर स्थित केवलादेव बर्ड सेंचुरी, रणथंभौर, सरिस्का अभयारण्य, सांभर झील व अन्य वेटलैंड्स जहां अधिक संख्या में पक्षी मिलते हैं, वहां विशेष निगरानी बरती जाए। गहलोत ने कहा कि किसी भी पक्षी की मसैत होने पर उसका सैंपल लैब में भेजा जाए और वैज्ञानिक विधि से मृत पक्षियों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही बरतने और तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर वायरस इंसान को भी प्रभावित कर सकता है।

पांचवें दिन बंद हुई बारिश, जम्मू-श्रीनगर हाईवे फिलहाल बंद

जम्मू । शनिवार रात से जारी बारिश मंगलवार देर रात से थम गई है। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी अनुसार अभी जम्मू में बारिश के आसार बने हुए हैं। कश्मीर में आज से मौसम आज से साफ हो जाएगा। बारिश थम जाने के बावजूद ठंड का प्रकोप बढ़ेगा।

कश्मीर बुधवार को लगातार चौथे दिन दुनिया के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है। श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग बंद है और भारी बर्फबारी के कारण हवाई यातायात भी निर्लंबित रहा। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अभी नहीं खुल सका है। कई स्थानों पर भूस्खलन के चलते जल्द जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने का आसार नहीं दिख रहे हालांकि सड़क से मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं लेह श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जितनी बर्फ पड़ी हुई है, उसे देखते हुए रास्ता खुलने की जल्द कोई संभावना नहीं दिख रही। ऐतिहासिक मुगल रोड भी बंद पड़ा हुआ है। जिसके चलते 45 सौ के करीब गाड़ियां फंसी हुई हैं। कश्मीर संभाग में न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी अनुसार- जम्मू का अधिकतम तापमान 16.9, न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा। पहलगाम का अधिकतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस रहा। गुलमर्ग का अधिकतम तापमान -1.4 जबकि न्यूनतम तापमान -3.5 डिग्री सेल्सियस रहा। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा का अधिकतम तापमान 14.2 जबकि न्यूनतम 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। भद्रवाह का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा। बर्फबारी व भूस्खलन के चलते जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुधवार को पांचवे दिन भी यातायात के लिए बंद रहा। हालांकि मौसम साफ होने पर सरकारी अमला राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए सुचारू करने में जुट गया है और अगर मौसम साफ रहता है तो अगले 24 घंटों के भीतर रास्ते में फंसे वाहनों को निकालने का काम शुरू हो गया। इस बीच आज बुधवार को भी लो-विजिब्लिटी होने के कारण जम्मू व श्रीनगर में सुबह के समय सभी फ्लाईट कैंसिल कर दी गई।

भटिंडी स्थित बेग कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्वे, आय छुपाने का है आरोप

जम्मू । आयकर विभाग ने बुधवार को भटिंडी स्थित बेग कंस्ट्रक्शन के घर व आफिस में सर्वे किया। विभाग का इस साल का यह पहला सर्वे है। बेग कंस्ट्रक्शन पर आय छुपाने का आरोप है और कंपनी की ओर से दायर आयकर रिर्टन में उचित आय न दिखाए जाने के संदेह में विभाग ने यह कार्रवाई की है। बेग कंस्ट्रक्शन ने जम्मू-कश्मीर में कई सरकारी योजनाओं में भी काम किया है और शहर के बड़े-बड़े ठेके लेकर विकास कार्य करवाती है। विभागीय टीमों ने बुधवार सुबह पुलिस व सीआरपीएफ की टीमों के साथ कंपनी के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। आयकर विभाग की चंडीगढ़ से विशेष टीमें आई थी जिन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। कुंजवानी-नरवाल हाईवे पर वेव मॉल के सामने भटिंडी में बेग कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक का घर है और इसी क्षेत्र में कंपनी का एक कार्यालय भी है। विभागीय टीमों ने यहां पहुंचने के बाद घर व कार्यालय को भीतर से बंद कर दिया और किसी को भी आनेजाने की इजाजत नहीं दी। आयकर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी की आय करोड़ों रुपये में है लेकिन पिछले कई सालों से वह अपनी आय के मुताबिक कर की अदायगी नहीं कर रही थी। सूत्रों का कहना है कि कंपनी के पार्टनर को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसलिए सालों से कर चोरी कर रहे थे। आयकर विभाग की ओर से बार-बार चेताने के बावजूद कंपनी की ओर से उचित आयकर न भरे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। आयकर विभाग की टीमें इस समय कंपनी के लेनदेन से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है ताकि उसकी आय का उचित आंकलन किया जा सके।

उत्तर गुजरात की सबसे बड़ी दूधसागर डेयरी के चुनाव में पूर्व मंत्री विपुल चौधरी गुट की करारी हार

अहमदाबाद । उत्तर गुजरात की सबसे बड़ी दूधसागर डेयरी के चुनाव में गुजरात के पूर्व मंत्री विपुल चौधरी के गुट की करारी हार हुई है। परिवर्तन पैनल के अशोक चौधरी को 15 में से 13 मत मिले हैं।

उत्तर गुजरात कि मेहसाना दूधसागर डेयरी के चुनाव को लेकर पिछले दो-तीन महीने से भारी उठापटक चल रही थी। करीब 4000 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली मेहसाना दूधसागर डेयरी के प्रबंधन मंडल पर कब्जा करने के लिए ट्रस्टी मंडल के दो गुट आमने-सामने थे। डेरी पर लंबे समय तक राज करने वाले विपुल चौधरी हाल 22 करोड़ रुपए के पोषाहार वितरण में अनियमितता तथा डेरी में करोड़ों रुपए की अनियमित लेनदेन के मामले में फंसे हुए हैं।

दूधसागर डेयरी से जुड़े ट्रस्ट के सदस्यों वह इसके सदस्यों ने मंगलवार को मतदान किया, 1129 सदस्यों में से 1117 सदस्यों ने

मतदान किया इस चुनाव में 99.11 प्रतिशत मतदान हुआ। इसमें अशोक चौधरी गुट की जीत हुई। इसके अलावा दूधसागर डेयरी के 15 डेरी सदस्यों में से 13 अशोक चौधरी के पक्ष में रहे विपुल चौधरी के पक्ष में केवल दो ही डेयरी सदस्य थे। गौरतलब है कि पिछले माही दूधसागर डेहरी में करोड़ों रुपए की हेरा फेरी के मामले में सीआइडी की क्राइम ब्रांच ने विपुल चौधरी की धरपकड़ की थी। विपुल चौधरी पर डेरी के कर्मचारियों को अतिरिक्त बोनस दिलाकर उनसे अपने खाते में करोड़ों की रकम जमा करवाने का मामला चल रहा है।

विपुल चौधरी ने इन पैसों से पोषाहार अनियमित मामले की रकम भरने तथा दिल्ली के ज्वेलर्स से सोना खरीद लिया था। उत्तर गुजरात की सबसे बड़ी दूधसागर डेहरी गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन से जुड़ी हुई है कथा दूधसागर ब्रांड के नाम से ही अपना अलग दूध घी दही तथा अन्य दूध प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। विपुल चौधरी के पिता ने ही इस दूधसागर डेयरी की स्थापना की थी तथा लंबे समय तक विपुल चौधरी इस डेरी के संचालक रहे लेकिन पोषाहार घोटाला मामले में फंसने के बाद उन्हें डेरी का प्रबंधन छोड़ना पड़ा था।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सूखा पड़ने के दौरान गुजरात की इस डेरी ने महाराष्ट्र सरकार को 22 करोड़ का पोषाहार दान के रूप में उपलब्ध कराया था। लेकिन गुजरात के सहकारी रजिस्ट्रार ने इसे अनियमितता बताते हुए विपुल चौधरी के खिलाफ एक केस दर्ज कराया था। इसकी रकम की भरपाई के लिए चौधरी ने डेरी के कर्मचारियों को अतिरिक्त बोनस दिलाकर अपने खाते में वापस धन ट्रांसफर करा लिया था। इस मामले में उनके खिलाफ फौजदारी केस चल रहा है।

गुजरात में आरएसएस की समन्वय बैठक: राममंदिर निर्माण व कोरोना पर मंथन

अहमदाबाद । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गांधीनगर में समन्वय बैठक का अहम मुद्दा होगा अयोध्या में भव्य राममंदिर का निर्माण। मंदिर के लिए धनसंग्रह में संघ की सभी संस्थाओं की मदद ली जाएगी। इसके अलावा कोरोना महामारी में संघ से जुडी संस्थाओं के सेवा कार्य की समीक्षा होगी। आरएसएस की तीन दिवसीय समन्वयक बैठक मंगलवार को गांधीनगर के उवारसद गांव के कर्णावती विश्वविद्यालय परिसर में शुरु हुई।

सरसंघ चालक मोहन भागवत, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, विहिप के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय सहित संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी व अन्य आनुषांगिक संगठनों पदाधिकारी इसमें शिरकत कर रहे हैं। राममंदिर के लिए धन संग्रह पर चर्चा, कोरोना महामारी के दौरान संघ के कार्य तथा किसान आंदोलन पर भी इसमें चर्चा होगी।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय अयोध्या में भव्य राममंदिर निर्माण की रुपरेखा पेश करेंगे। साथ ही संघ की संस्थाओं के जरिए देश - विदेश से धन संग्रह के अभियान को तय समय तक पूरा करने पर भी चर्चा होगी। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार के अनुसार संघ से जुडे भाजपा, विहिप, भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय विध्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्र सेविका समिति, स्वदेशी जागरण मंच आदि संगठनों के डेढ सौ से अधिक पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। संघ के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीन जैन के अनुसार हर दो साल में आरएसएस की समन्वय बैठक का आयोजन होता है जिसमें बीते समय में तथा वर्तमान में देश के घटनाक्रम व विविध राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। संघ के हरेक संगठन के अध्यक्षव महासचिव अपने संगठन के कामकाज की जानकारी देते हैं तथा आवश्यक जानकारियां आपस में साझा कर उस विषय पर भविष्य की योजना तैयार की जाती है। गुरुवार को संघ की ओर से इस बैठक की जानकारी मीडिया को दी जाएगी तथा संघ के भावी एजेंडे की घोषणा होगी।

भाजपा के नित्यानंद राय ने कहा- भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रहा और बंगाल लगातार पीछे जा रहा

कोलकाता । केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने मंगलवार को ममता बनर्जी सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि यहां की विधि व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के जनसंपर्क अभियान के क्रम में मंगलवार को दक्षिण 24 परगना जिले के महेशशतला में राय ने कहा कि एक तरफ जहां भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार होकर लगातार आगे बढ़ रहा है वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार के कारण राज्य लगातार पीछे की ओर जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार की 80 से यादा योजनाएं जो गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है उनमें से दर्जनों योजनाएं बंगाल में लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार यहां के गरीब लोगों को केंद्रीय योजनाओं से वंचित कर रही है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। राय ने कहा कि इसको लेकर बंगाल की पूरी जनता का ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा दिखाई पड़ने लगा है और इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री ने लोगों के आक्रोश को देखते हुए मजबूरी में एक दिन पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू करने के संबंध में कुछ बात कहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो हर साल देशभर के प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जा रही है, उससे भी बंगाल के किसानों को वंचित रखा गया। यही नहीं आयुष्मान भारत योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, वह भी अब तो बंगाल में लागू नहीं है। उन्होंने मनरेगा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी ममता सरकार पर निशाना साधा। राय ने कहा कि मनरेगा में जो मजदूरी मजदूरों को मिलना चाहिए वह उनको नहीं मिलकर तृणमूल के ठेकेदारों को मिल रहा है। इस तरह के हालात पूरे बंगाल में हैं।

उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता ममता सरकार के हर कृत्य का जवाब देगी। राय ने इस दिन महेशतला इलाके में बूथ नंबर 97 व 98 में गृह संपर्क अभियान चलाया। उन्होंने इस दौरान

घर-घर जाकर लोगों को मोदी सरकार के कार्यों के बारे में बताया। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता व कार्यकर्ता भी थे।

तृणमूल कांग्रेस ने कहा- बंगाल में सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लोगों के लिए काम किया

कोलकाता । बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले वर्षों में विकास के कई सारे काम किए हैं और शहरों-गांवों में बड़े पैमाने पर सड़क और पुलों का निर्माण कराया गया है। राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि बंगाल में किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने विकास के इतने काम नहीं किए।

मुखर्जी ने कहा, ''हमने असाधारण काम किए हैं, समूचे राज्य में शहरों और गांवों में सड़कों और पुलों का निर्माण किया गया। हमने जितना काम किया पूर्ववर्ती सरकारें कभी उतना काम नहीं कर पाईं।'' उन्होंने कहा कि 'बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना' के तहत तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 16,561 करोड़ रुपये की लागत से 35,611 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया। उन्होंने कहा, ''सड़क और पुल क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में बड़ा योगदान देते हैं और हमारी मुख्यमंत्री इससे अवगत हैं। चक्रवात एम्फन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में भी पुनर्निर्माण और मरम्मत के काम दिखते हैं।''

सड़क निर्माण के क्षेत्र में बंगाल देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने मंगलवार को दावा करते हुए कहा कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में बंगाल देश में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने सूचित किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नई परियोजना की घोषणा की है। राज्यभर में सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत कुल 12,000 किलोमीटर तक सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इस परियोजना के दायरे में रायभर की 7,000 सड़कें आएंगी। राय सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2021 तक 690 किलोमीटर सड़क का काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सुब्रत मुखर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेक इन इंडिया 'वास्तव में बेचो इंडिया' है। सेल से रेल तक सबकुछ बेचा जा रहा है। राष्ट्र की हर सार्वजनिक संपत्ति बेचने की कोशिश चल रही है। केंद्र सरकार ने पिछले छह वर्षों में बीएसएनएल को बर्बाद करके रख दिया है। उसने बीएसएनएल के 75,000 कर्मचारियों को वीआरएस लेने के लिए बाध्य किया।

केंद्र सरकार बंगाल केमिकल्स, एलॉय स्टील प्लांट, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड समेत विभिन्न सार्वजनिक उपकरणों को भी बेचने की तैयारी में है। तृणमूल कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी और इसका जोरदार विरोध जारी रखेगी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ ओडिशा सरकार की बड़ी कार्रवाई: सात भ्रष्ट अधिकारियों को जबरन थमाया सेवानिवृत्ति पत्र

भुवनेश्वर । भ्रष्ट एवं लापरवाह अधिकारियों को हटाने का मानों संकल्प ले चुकी ओडिशा सरकार ने आज फिर सात भ्रष्ट अधिकारियों को पुनः जबरन सेवानिवृत्ति का पत्र थमा दिया है। इन्हें मिलाकर सरकार अब तक 104 लोग जबरन सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आज जिन सात लोगों को जबरन सेवानिवृत्त किया गया है, उसमें एक जेल डीआईजी, एक कमांडेंट, एक डीएसपी, एक डिप्टी कमांडेंट तथा दो खदान अधिकारी एवं एक सीडीपीओ शामिल हैं।

लापरवाह एवं भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। पिछले एक साल में 104 लापरवाह एवं भ्रष्ट अधिकारियों को नवीन सरकार ने सरकारी नौकरी से विदा किया है। 30 दिसम्बर को राज्य सरकार ने छह भ्रष्ट अधिकारियों जबरन सेवानिवृत्त कर दिया था। जबरन सेवानिवृत्ति पाने वाले अधिकारियों में जेल विभाग के डीआईजी गोपबन्धु मलिक, डीएसपी गौतम मलिक, ओडिशा सशस्त्र पुलिस सेवा कमांडेंट एकांत प्रिय नायक, जूनियर खदान अधिकारी सत्यव्रत राउत, ओडिशा सशस्त्र पुलिस सेवा के डिप्टी कमांडेंट देवेन्द्र नाथ बेहेरा, जूनियर खदान अधिकारी रमेश चन्द्र पंडा एवं कोरापुट नंदपुर के सीडीपीओ स्निग्धाराणी मिश्र शामिल हैं। डीआईजी गोपबन्धु मलिक जेल वार्ड के चयन के लिए बनी कमेटी के मुख्य के तौर पर काम करते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर चयन प्रक्रिया में पक्षपात किया था। जेल विभाग में उनका कार्यकलाप संतोषजनक नहीं था एवं उनकी ईमानदारी पर भी संदेह था।

स्निग्धाराणी कोरापुट नंदपुर के सीडीपीओ के तौर पर कार्य करते समय उनके नाम पर दो विजिलेंस मामला था। 2016 में 80 लाख रुपये आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में मुकदमा दायर किया गया था। अक्टूबर 2020 छत्तु के बिल के लिए स्वयं सहायक समूह के एक सदस्य से 1 लाख 75 हजार रुपये घूस लेते पकड़े गए थे और उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया था।

ओडिशा सशस्त्र पुलिस सेवा में कार्यरत एकांत प्रिय नायक पर अपने नीचे कार्य करने वाले कर्मचारी के साथ मारपीट करने का आरोप है। ऐसे में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है एवं उन्हें नौकरी से निलंबित किया गया है। एक शराबी तथा अयोग्य अधिकारी के तौर पर उनके ऊपर कई आरोप हैं। डीएसपी गौतम मलिक के खिलाफ दो फौजदारी मामला है और उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। उनकी ईमानदारी पर संदेह था।

ओडिशा सशस्त्र पुलिस सेवा के डिप्टी कमांडेंट के तौर पर कार्य करने वाले देवेन्द्र नाथ बेहेरा के नाम पर जंगल से लकड़ी चोरी करने के आरोप में फौजदारी मामला दर्ज है। सरकारी गाड़ी में अपने निचले कर्मचारियों से जबरन लकड़ी चालान करवाने के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जूनियर खदान अधिकारी सत्यव्रत राउत के खिलाफ 5 विजिलेंस मामला है। उनकी ईमानदारी पर संदेह था। दायित्व में लापरवाही, दुर्व्यवहार आदि गम्भीर आरोप में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई पहले से की गई है। वर्तमान में ये निलंबित हैं। जूनियर खदान अधिकारी रमेश चन्द्र पंडा के खिलाफ तीन विजिलेंस मामला है। उनकी ईमानदारी पर संदेह होने के साथ ही दायित्व में उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार जैसे गम्भीर मामले हैं। यह भी वर्तमान समय में निलंबित चल रहे हैं।

विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम चुनाव की संभावना बेहद कम

सिलीगुड़ी । इस वर्ष होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव कराना संभव नहीं होगा। सिलीगुड़ी नगर निगम के आधिकारिक सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कोरोनावायरस महामारी के चलते निगम चुनाव पिछले वर्ष मई जून में कराना संभव नहीं हो पाया, जबकि इस वर्ष अप्रैल-मई में राज्य विधानसभा चुनाव कराया जाना एक तरह से से निश्चित है। ऐसी स्थिति में नगर निगम चुनाव जून-जुलाई से पहले करा पाना संभव नहीं होगा।

बताया गया कि नगर निगम चुनाव तथा पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, तथा जब राज्य सरकार सरकार चाहती है, तभी राज्य चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है। जबकि विधानसभा चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा कराई जाती है। इसलिए जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव समय पर कराए गए, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी राज्य विधानसभा चुनाव समय पर अप्रैल-मई में कराए जाने की पूरी संभावना है। जबकि चुनाव की घोषणा फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर के 15 मार्च से पहले की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य के 110 नगर निकायों का चुनाव इस वर्ष जून के बाद ही कराए जाएंगे। ऐसी ही स्थिति सिलीगुड़ी महकमा में पंचायत चुनाव को लेकर के भी है।

सिलीगुड़ी महकमा में मग्मा परिसर से लेकर ग्राम पंचायत तक का कार्यकाल पिछले वर्ष नवंबर में ही खत्म हो गया है। इस तरह से पंचायत चुनाव भी जून के बाद ही कराए जाने की प्रबल संभावना है।

उल्लेखनीय है कि सिलीगुड़ी नगर निगम का कार्यकाल सिलेबस 20 मई को खत्म हो गया नगर निगम का कार्यकाल खत्म होने के बाद नगर निगम के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासक नगर निगम के तत्कालीन मेयर अशोक भट्टाचार्य को ही बनाया गया। हालांकि राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सिलीगुड़ी नगर निगम समेत राज्य के अन्य नगर निगम का चुनाव कराने की मांग को लेकर माकपा नेता तथा सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासकीय बोर्ड के चेयर पर्सन अशोक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखे थे। उनका कहना था कि कोरोना काल में ही जब केरल, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर हरियाणा समेत अन्य जगहों पर पंचायत, जिला परिषद व नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं, तो फिर पच्छिम बंगाल में क्यों नहीं कराए जा सकते हैं।

ठाणे कोर्ट में किशोरी से दुष्कर्म के तीनों आरोपियों को 5 साल की सजा, जुर्माना भी लगा

ठाणे । महाराष्ट्र के ठाणे की विशेष POCSO अदालत ने 2014 में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी तीन युवकों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत में ये आदेश 4 जनवरी को पारित किया गया था और इसकी एक प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई थी।

न्यायाधीश एस पी गोंधलेकर ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। उनमें से प्रत्येक आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने अदालत को बताया कि 14 अप्रैल 2014 को पीड़िता की उम्र 15 वर्ष थी वह महाराष्ट्र के कलवा में वाघोबा नगर में अपने घर के पास शौच के लिए गई थी। तभी आरोपियों ने उसे पकड़ लिया।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि अभियुक्तों ने लड़की के मुंह पर रूमाल रखा और जब वह बेहोश हो गई, तो वे उसे पास की झाड़ियों में ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर, कलवा पुलिस ने बाद में एक मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं इसलिए उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया गया है।

रतन टाटा की कार के नंबर वाली प्लेट लगा घूम रही थी महिला, कटा चालान खुली पोल

मुंबई । मुंबई पुलिस ने व्यवसायी रतन टाटा की कार का नंबर इस्तेमाल करने के मामले में एक कंपनी की निदेशक महिला को पकड़ा है। आरोपी महिला पर यातायात उल्लंघन मामले को लेकर जुर्माना लगाया गया है और आईपीसी की धारा 420 और 465 और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला तब सामने आया जब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर रतन टाटा को चालान भेज दिया गया। पुलिस के पूछने पर महिला ने बताया कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी ज्योतिषी के कहने पर वह इस नंबर का प्रयोग कर रही थी।

मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना मंगलवार रात की है आरोपी महिला थी इसलिए पूछताछ के लिए उसे रात के समय थाने में नहीं बुलाया गया। महिला को बुधवार को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया। मामला तब समझ में आया जब महिला की गलती पर ई चालान रतन टाटा को भेज दिया गया। चालान का जवाब देते हुए टाटा समूह के अधिकारियों ने बताया कि उनकी कार से किसी भी प्रकार का यातायात उल्लंघन नहीं किया गया है। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया, जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने कैमरे के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरु कर दिये जहां से ई चालान जारी किया गया था। जांच में सामने आया कि जिस कार ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया है उस पर रतन टाटा की कार के नंबर की प्लेट लगी हुई है।

जांच में सामने आया कि आरोपी महिला एक कार कंपनी की निदेशक है। पुलिस ने महिला और उसकी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। माटुंगा पुलिस स्टेशन में कार को भी जब्त कर लिया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, एक ज्योतिष के कहने पर आरोपी महिला ने मूल नंबर प्लेट में फेरबदल कर नकली नंबर प्लेट का प्रयोग किया था। सच्चाई सामने आने के बाद अब यातायात पुलिस ने रतन टाटा के स्वामित्व वाली कार को भेजे गए सभी ई चालान अब आरोपी महिला को भेज दिये हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कभी भी इस तरह के फर्जी नंबर का प्रयोग न करें नहीं तो आप मुसीबत में घिर सकते हैं।

गुटखा माफिया है सरकार का अगला टारगेट : डॉ. मिश्रा

भोपाल (एजेंसी)। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर पुलिस प्रशासन की ड्रग माफियाओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हर प्रकार के माफिया को सरकार नेस्तनाबूद कर देगी। डॉ. मिश्रा ने कहा कि सरकार का अगला टारगेट गुटखा माफिया है।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा है कि शीघ्र ही सरकार गुटखा माफिया के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि हमने अब तक जो कहा, वो करके दिखाया है। हमारी सरकार बनने के बाद भू-माफियाओं के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई जारी है। ड्रग माफियाओं के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अगला नंबर गुटखा माफियाओं का है। सरकार कार्रवाई करने में कतई भी पीछे नहीं हटेगी। हरेक माफिया को ढूंढ-ढूंढ कर खत्म किया जाएगा। प्रदेश में कायम शांति का राज बनाए रखने के साथ ही सुखी और समृद्ध आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश बनाने के मार्ग में आने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा।

पोल्ट्री पर बर्ड फ्लू का प्रमाण नहीं, प्रदेश में बंद नहीं होंगी मांस दुकानें

पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह ने कलेक्टरों को दिए निर्देश

भोपाल (एजेंसी)। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि प्रदेश के पोल्ट्री फार्मों और बैकयार्ड कुक्कुट में किसी प्रकार से मुर्गियों में अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना नहीं मिली है। इसलिए मांस की दुकानों पर बिक्री संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

ये दुकानें पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता के साथ यथावत खुली रहेंगी। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि कुक्कुट-पालकों और व्यावसाइयों के साथ बैठक कर बर्ड फ्लू से बचाव, पोल्ट्री फार्मों में साफ-सफाई और जन-सामान्य को कुक्कुट उत्पादों को अच्छी तरह से पकाकर उपयोग में लाने की जानकारी दें। श्री पटेल ने बताया कि कौओं में पाया जाने वाला वायरस एच 5 एन 8 है, जबकि मुर्गियों में सामान्यतः वायरस एच 5 एन 1 होता है। भोपाल में राज्य-स्तरीय और सभी जिलों में जिला-स्तरीय कंट्रोल-रूम की स्थापना कर दी गई है। कुक्कुट पालकों, व्यवसाइयों और लोगों को बर्ड फ्लू के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा है। सभी जिलों को भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार कार्यवाही, सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

एसीएस कंसोटिया ने सभी जिलों के विभागीय अधिकारियों से लिया फीडबैक

अपर मुख्य सचिव पशुपालन जेएन कंसोटिया ने बुधवार को वीसी के माध्यम से सभी जिलों के विभागीय जिलाधिकारियों को बर्ड फ्लू से बचाव और नियंत्रण के दिशा-निर्देश देते हुए वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कुक्कुट-पालकों के साथ बैठक आयोजित करने, बॉयो सिक्यूरिटी मापदंड का पालन सभी कुक्कुट प्रक्षेत्रों, कुक्कुट बाजारों आदि में सुनिश्चित करने निर्देश दिए। श्री कंसोटिया ने निर्देश दिए` कि यदि कहीं कोई कौआ या पक्षी मृत पाया जाता है, तो तत्काल सैंपल भारतीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल को भेजें। प्रदेश के 11 जिलों में कौओं की मृत्यु की सूचना मिली है। इनमें केवल इंदौर, मंदसौर और आगर-मालवा में ही वायरस की पुष्टि हुई है।

कलेक्टर करेंगे बर्ड फ्लू बचाव की तैयारियों की समीक्षा

श्री कंसोटिया ने सभी जिला कलेक्टरों से पशुपालन, वन, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय और अन्य समन्वयक विभागों की बैठक आयोजित कर बर्ड फ्लू से संबंधित तैयारी एवं आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिये संसाधन एवं सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे एक्शन प्लान ऑफ एवियन इन्फ्लूएंजा-2015 के अनुरूप प्रावधानित कार्यवाही और सर्विलांस सुनिश्चित करें।

सभी जिलों में बनाए कंट्रोल-रूम

प्रदेश के सभी जिलों में बर्ड फ्लू कंट्रोल-रूम की स्थापना की गई है। भोपाल में राज्य-स्तरीय कंट्रोल-रूम का क्रमांक 0755-2767583 है। सूचना मिलते ही रेपिड रिस्पांस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही की जा रही है। मुर्गियों, कौवों, प्रवासी पक्षियों आदि में असामान्य मृत्यु, बीमारी की सूचना मिलते ही तत्काल सैम्पल इकट्ठा कर उसका डिस्पोजल, डिसइंफेक्शन और सेनेटाइजेशन आदि किया जा रहा है।

मंत्री गोपाल भार्गव ने हस्त शिल्प विकास निगम की बैठक में दिए निर्देश

समय की मांग के अनुसार तैयार कराए जाएं खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पाद

भोपाल में बनेंगे खादी ग्रामोद्योग के तीन नए आउटलेट

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश के कुटीर, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए कुटीर एवं खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत तैयार किए उत्पाद आधुनिक फैशन एवं समय की मांग के अनुसार तैयार कराए जाएं। इसके लिये विशेषज्ञों की मदद ली जावे। उन्होंने यह निर्देश मंत्रालय में आयोजित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, संत रविदास हस्त शिल्प विकास निगम एवं मप्र राज्य रेशम विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित की बैठक में दिए।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि कुटीर, खादी एवं ग्रामोद्योग के अंतर्गत गठित निगम एवं फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इससे उनके जीवन-स्तर में सुधार हो सकेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि रेशम, खादी से उत्पादित वस्त्रों की डिजाइनिंग के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएं। उन्होंने रेशम वस्त्रों की मॉडर्न डिजाइनिंग के लिये विभागीय अधिकारियों की टीम मार्केट सर्वे के लिए जयपुर भेजने के निर्देश भी दिए। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड शीघ्र ही भोपाल में तीन नवीन आउटलेट प्रारंभ करने जा रहा है। इसकी अनुमति भी बोर्ड की बैठक में दे दी गई है। यह आउटलेट वल्लभ भवन की एनएक्सजी-2, मालवीय नगर और संजीवनी प्राकृत परिसर में प्रारंभ किये जायेंगे, जिनमें विंध्य वैली के उत्पाद भी विक्रय के लिए रखे जाने का निर्णय भी लिया गया।

बुधवार को भोपाल में प्रदेश के लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में संत रविदास हस्त शिल्प विकास निगम की बैठक हुई।

उत्पाद अमेजन एवं फ्लिप कार्ट पर भी उपलब्ध

बाजार के बदलते स्वरूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिये खादी ग्रामोद्योग के सभी विंध्य वैली उत्पाद अब अमेजन एवं फ्लिप कार्ट पर भी उपलब्ध रहेंगे। दोनों कम्पनियों के साथ हुए एमओयू को भी बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई। इसके साथ ही हस्तशिल्प विकास निगम के मृगनयनी शोरूम में भी विंध्य वैली और रेशम के उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। मंत्री श्री भार्गव ने व्यापक आधुनिक प्रसार माध्यमों से रेशम, खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों के विज्ञापन के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में प्रमुख सचिव कुटीर एवं खादी ग्रामोद्योग अनिरुद्ध मुखर्जी, प्रबंध संचालक हस्तशिल्प विकास निगम राजीव शर्मा, प्रबंध संचालक खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड गौतम सिंह सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।

प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण की रिहर्सल कल, सभी तैयारियां पूरी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने दिए पूरी गंभीरता से ड्राय रन करने के निर्देश

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि राज्य में आगामी दिनों में होने वाले कोविड-19 टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

श्री चौधरी ने बुधवार को मंत्रालय में कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियों के सिलसिले में आयोजित समीक्षा बैठक में टीकाकरण दलों और वैक्सीन के भंडारण, लॉजिस्टिक आदि कार्यों से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आठ जनवरी को प्रदेश में होने वाले टीकाकरण की रिहर्सल (ड्राय रन) को पूरी गंभीरता से करें।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीकाकरण की सभी तैयारियां और व्यवस्थाएं चुस्त-दुरूस्त रखी जाएं। टीकाकरण केंद्र में प्रतीक्षा कक्ष, टीकाकरण कक्ष और ऑब्जरवेशन कक्ष रहेंगे। टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण दल में चार वैक्सीन ऑफीसर होंगे। टीकाकरण केंद्रों पर संचालित कार्यवाही को मॉनिटरिंग करने के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को पर्यवेक्षण का दायित्व दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की पूरी कार्यवाही कोविड प्लेटफार्म के माध्यम से होगी। हैल्थ केयर वर्कर्स में शासकीय और अशासकीय चिकित्सालयों के चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी शामिल रहेंगे। टीकाकरण वैक्सीन आने और टीकाकरण की तारीख तय होने के बाद शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश में टीकाकरण के लिए 1158 कोल्ड चेन स्टोरेज हैं। एक सेशन में एक वैक्सीन केंद्र पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि राज्य स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम से पूरे प्रदेश में होने वाले टीकाकरण अभियान पर लगातार नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हैल्थ केयर वर्कस के बाद, दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कस का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे स्वयं व्यवस्थाओं का जायजा लेने कंट्रोल रूम, कोल्ड चेन और टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण करेंगे।

मंत्री राजपूत ने संभाला परिवहन एवं राजस्व विभाग का कार्यभार

भोपाल, (प्रसं)। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पूजा-अर्चना के बाद बुधवार शाम 5.15 बजे परिवहन एवं राजस्व विभाग के मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर श्री राजपूत के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता सिंह राजपूत एवं पुत्र आकाश सिंह राजपूत भी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री पटेल ने रातीबड़ में लगाई चौपाल

किसानों ने हाथ उठाकर किया नए कृषि कानूनों का समर्थन

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश के कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। वे रातीबड़ में आयोजित किसान चौपाल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदों से अवगत कराया। चौपाल में किसानों ने अपने हाथ उठाकर नए कृषि कानूनों का पुरजोर समर्थन किया।

मंत्री श्री पटेल ने कृषकों से मुखातिब होते हुए कहा कि नवीन कृषि विधेयकों और महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से किसानों की आय में कई गुना वृद्धि होगी। इनके लागू होने से अब किसान सिर्फ खेती ही नहीं करेंगे, उद्योग-धंधे स्थापित करने में भी समर्थ हो सकेंगे। अब किसानों को उनके गाँव की जमीनों का मालिकाना हक प्राप्त होने लगा है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से ही सबसे पहले हरदा के रामभरोस विश्वकर्मा को मालिकाना हक मिला और प्लाट, कुआं और दो पेड़ सरकार द्वारा सड़क मार्ग के लिएअधिग्रहीत करने पर मुआवजे के रूप में लगभग 21 लाख रुपए की राशि मिली। यदि यह योजना लागू नहीं होती, तो रामभरोस को कुछ भी नहीं मिलता। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनांतर्गत मालिकाना हक प्राप्त होते ही किसान और ग्रामीण विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लेने में सक्षम हो जायेंगे। किसान खेती के साथ-साथ प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ लेते हुए कृषिगत व्यवसाय और अन्य व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकेंगे। इस प्रकार से किसानों की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और वे आत्म-निर्भर मप्र और आत्म-निर्भर भारत की स्थापना में अपनी महती भूमिका निभाएंगे।

कृषि मंत्री ने बर्फानी बाबा को अर्पित की श्रद्धांजलि : कृषि मंत्री पटेल ने रातीबड़ स्थित बर्फानी आश्रम पहुंचकर बाबा बर्फानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आश्रम के संचालक बाबा बर्फानी का गत 23 दिसंबर को महाप्रयाण हो गया था, उनकी आत्मा की शांति के लिए आश्रम पर आज पूजन किया गया। कृषि मंत्री कमल पटेल इसी आयोजन के लिए रातीबड़ पहुंचे थे।

मुख्यमंत्री आज करेंगे किचन शेड और किचन गार्डन का वर्चुअल लोकार्पण

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, सात जनवरी को दोपहर तीन बजे मिंटो हॉल में प्रदेश में बनाए गए 2500 किचन शेड एवं 7100 किचन गार्डन (पोषण वाटिका) का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इनका निर्माण कोरोना काल में किया गया है। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल आदि उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान इस अवसर पर मध्यान्ह भोजन बनाने वाले कुछ रसोइयों, ग्रामों के सरपंचों तथा शाला प्रबंधन समिति के सदस्यगणों से वीसी के माध्यम से चर्चा भी करेंगे।कार्यक्रम का दूरदर्शन भोपाल के माध्यम से सीधा प्रसारण होगा।

मुख्यमंत्री मदद योजना के नियमों में संशोधन

अजा कल्याण विभाग ने जारी किए आदेश

भोपाल, (एजेंसी)। आदिम-जाति कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री मदद योजना के नियमों की कुछ कंडिकाओं में संशोधन किये हैं। इस संबंध में विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं।

संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री को अब ग्राम पंचायत सचिव प्राप्त कर स्टॉक पंजी में संधारित किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम में अनुसूचित-जनजाति के परिवार में सामाजिक संस्कारों के कार्यक्रम के लिये उक्त सामग्री संबंधित परिवार को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सामग्री प्रदाय किए जाने की जानकारी संधारित करने के लिए एक पंजी तैयार की जाएगी। उक्त पंजी में समय-समय पर जिस परिवार को उपयोग के लिए सामग्री दी जाएगी, उसका विवरण पंजी में लिखा जाएगा। मध्यप्रदेश के विभिन्न जन-जातीय समुदाय में जन्म, मृत्यु आदि संस्कारों पर उत्सव करने की परंपरा रही है। इन अवसरों पर सामाजिक भोज का आयोजन` किया जाता रहा है। ऐसे अवसरों पर निर्धनता के कारण कई जन-जातीय परिवार भोज आदि की व्यवस्था में कठिनाई का सामना करते हैं। जन-जातीय परिवारों को इस समस्या से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के 89 जन-जातीय विकासखंडों में मदद योजना संचालित की है। योजना के अंतर्गत बच्चे का जन्म होने पर उत्सव के लिए 50 किलो अनाज और मृत्यु होने पर भोज के लिए एक क्विंटल अनाज संबंधित परिवार को निर्धारित दर पर उचित मूल्य की दुकान से उपलब्ध कराया जा रहा है।

मध्यप्रदेश तीन नागरिक केंद्रित सुधार पूरा करने वाले दो राज्यों में शामिल

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित चार नागरिक केंद्रित सुधारों में से तीन सुधारों को पूरा करने वाले पहले समूह में शामिल दो राज्यों में शामिल है। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। मध्यप्रदेश में वन नेशन-वन राशन-कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अर्बन लोकल बॉडी रिफार्म पूरे कर लिए गए हैं। इन सुधारों के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा अभी हाल में शुरू की गई राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 660 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मध्यप्रदेश को स्वीकृत की गई है। आंध्र प्रदेश को 344 करोड़ रुपए मिलेंगे।

केंद्र से पूंजीगत व्यय के लिए मिलेंगे अतिरिक्त 660 करोड़

केंद्रीय वित्त मंत्री ने 12 अक्टूबर, 2020 को आत्म-निर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में इस योजना की घोषणा की थी। पूंजीगत व्यय के लिए यह अतिरिक्त वित्तीय सहायता मध्यप्रदेश को अतिरिक्त ऋण के लिए जारी की गई अनुमति के अलावा दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान कर राजस्व कमी से उत्पन्न वित्तीय स्थिति से निपटने में राज्यों की मदद करना है। केंद्र सरकार ने प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकारों को विशेष सहायता देने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा मिलेगा।

ये हैं चार सुधार

वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित चार नागरिक केंद्र सुधार में से पहला वन नेशन-वन राशन-कार्ड, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तीसरा अर्बन लोकल बॉडी रिफार्म और चौथा पावर सेक्टर रिफार्म है। इन चार सुधार में से 31 दिसंबर, 2020 तक कम से कम तीन सुधार करने वाले राज्यों को यह विशेष सहायता उपलब्ध कराई गई है।

आदिवासियों पर कोई भी अत्याचार हो तो उसकी सूचना प्रदेश कांग्रेस को दें

कमलनाथ ने अपने निवास पर आदिवासी नेताओं को किया संबोधित

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उनके 15 माह के शासनकाल में राज्य में आदिवासियों के हित में अनेक निर्णय लिए गए हैं। श्री कमलनाथ ने बुधवार को यहां अपने निवास पर पार्टी के आदिवासी वर्ग के नेताओं को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही आदिवासी वर्गों के हितों की संरक्षक रही है और जब वे मुख्यमंत्री थे, तब आदिवासियों के हित में अनेक निर्णय लिये गए। उन्होंने बैठक में मौजूद नेताओं से कहा कि राज्य में आदिवासियों पर अत्याचार संबंधी कोई भी घटना हो, उसकी सूचना प्रदेश कांग्रेस को दी जाए। वे इन मामलों को भी उठाकर आदिवासियों को न्याय दिलाएंगे। श्री कमलनाथ ने आरोप लगाया कि वहीं भाजपा ने आदिवासियों के हित में कार्य नहीं किए। बैठक में मौजूद अन्य नेताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही आदिवासी वर्ग की हितैषी पार्टी रही है। उन्होंने 15 माह की कमलनाथ सरकार में आदिवासियों के हित में उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। बैठक में प्रमुख रूप से आदिवासी नेता व प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री बाला बच्चन, हनी बघेल, औंकार मरकाम, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, नन्हेलाल धुर्वे, तिलकराजसिंह, अभिजीत शाह सहित अन्य आदिवासी नेता व विधायकगण उपस्थित थे। बैठक का संचालन प्रदेश कांग्रेस आदिवासी विभाग के अध्यक्ष अजय शाह ने किया।

बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने निकाला ट्रैक्टर मार्च

भोपाल (एजेंसी)। कांग्रेस ने किसानों की समस्या को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में विशाल ट्रेक्टर रैली निकाली जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अलावा पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी भी शामिल हुए।

रैली में कांगेस नेताओं ने रेहटी से प्रारंभ हुई यह रैली नसरुल्लागंज तक पहुंची और इसके बाद आयोजित की गई सभा के दौरान भाजपा द्वारा लाए गए नए कृषि कानून की कमियां, इससे होने वाले नुकसान और किसानों को आने वाली परेशानियों पर बात की गई।प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेशभर में लगातार किए जा रहे किसान सम्मेलन के जरिए किसानों को इस बात का यकीन दिलाया जा रहा है कि कांग्रेस ही उनकी सच्ची हमदर्द है। बुधवार को रेहटी से नसरुल्लागंज तक निकाले गए ट्रेक्टर रैली के दौरान कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि वे सब किसानों के साथ हैं और उनके अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई जारी रखेंगे।

जानकारी के मुताबिक किसान सम्मेलन की कड़ी में अगला कार्यक्रम गुरुवार को देवास में आयोजित किया जाएगा। देवास जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किए जाने वाले इस आयोजन में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मप्र कांग्रेस के जिला प्रभारी योगेश यादव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया आदि शामिल रहेंगे।

उर्वशी रौटेला ने बर्थडे पर मां को दिया सरप्राइज, बोलीं उनके बिना कुछ भी नहीं हूं

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, वह अकसर अपने तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ साझा करती नजर आ जाती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से साझा की हैं। उर्वशी ने अपनी मॉम से गोल्ड प्लेटिड केक कटवाया। इन तस्वीरों में उर्वशी ब्लू कलर के आउटफिट में काफी खूबसूरत लग रही हैं, वहीं, उर्वशी की मां मीरा रौटेला ब्लैक कलर के गाउन में नजर आ रही हैं। उर्वशी रौतेला ने अपनी मां के जन्मदिन पर एक इमोशनल नोट भी लिखा। अभिनेत्री ने लिखा, मां मीरा रौटेला के जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। मैं चाहूंगी कि मेरी मां को पता चले कि मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से दुनिया को हासिल करूंगी, आई लव यू मां। प्रत्येक बीतते दिन के साथ मैं आपकी आभारी हूं, क्योंकि आपने मुझे गर्मजोशी, मार्गदर्शन, प्यार और अपना दिल दिया है। उन्होंने कहा, आप वो हैं, जो मुझे बिना शर्त प्यार करती हैं। चाहे मैं सही रास्ते पर रहूं या गलत। आपका जगह कोई नहीं से सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, मैं जहां भी जाऊंगी तुम हमेशा मेरे लिए रहोगी। थैंक यू मां। उर्वशी रौटेला के वर्क फ्रंट की बात करे तो वह हाल ही में फिल्म 'वर्जिन भानुप्रिया' में नजर आई थीं। उनका एक और वीडियो सॉन्ग 'तेरी लोड वे' भी रिलीज के लिए तैयार है। उनकी तेलुगू और हिन्दी थ्रिलर फिल्म 'ब्लैक रोज' की शूटिंग भी हाल ही में खत्म हुई है।

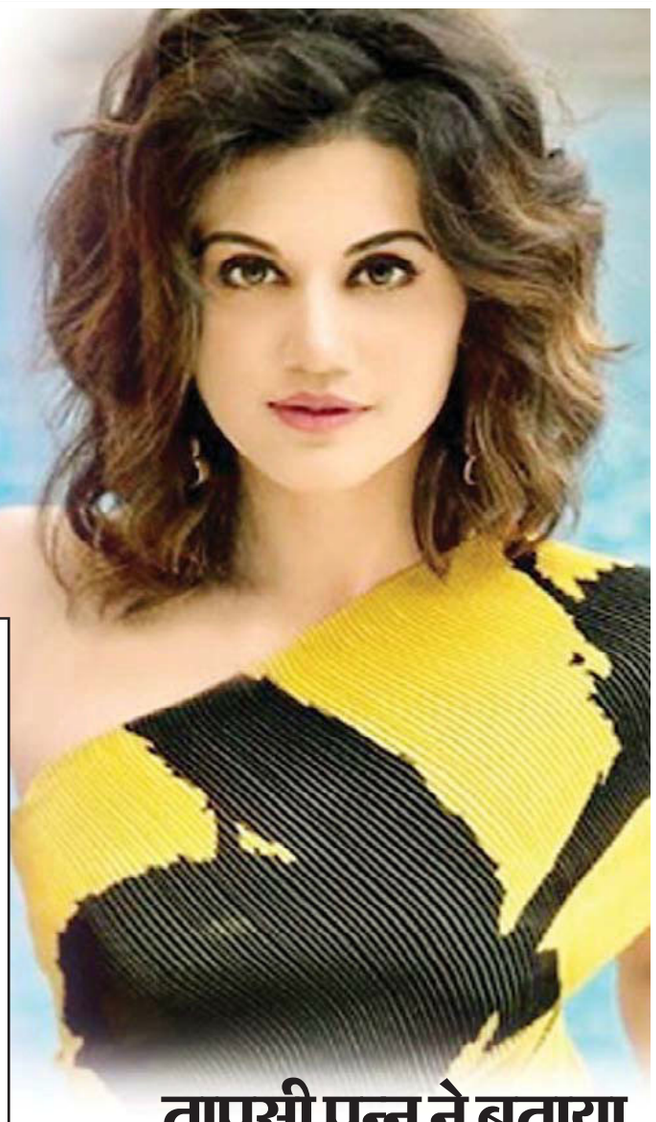

राखी सावंत को परेशान करने पर सलमान खान ने लगाई फटकार

बिग बॉस 14 के घर में हर दिन नए ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। घर में कंटेस्टेंट्स के बीच कापी मतभेद देखने को मिल रहा है। इस वीकेंड का वार में सलमान अच्छे मूड में नजर नहीं आएंगे वो घरवालों को जमकर फटकार लगाएंगे। दरअसल इस वाले हफ्ते में राखी के अलग-अलग रुप देखने को मिले और घरवालों ने जमकर राखी को परेशान किया है। ऐसे में सलमान ने शो शुरु होते ही घरवालों को इस बात के लिए फटकार लगाई। साथ ही रुबीना को नसीहत भी दे ड़ाली। सलमान खान ने राखी और जैस्मीन का जो झगड़ा हुआ था उसपर कहा कि 'उन्होंने जो भी किया है, उसे स्वीकारा नहीं जा सकता है। सलमान ने जैस्मीन को राखी से माफी मांगने के लिए कहा। साथ ही जैस्मीन को कहा कि वो एक बच्चे की तरह बर्ताव करना बंद करे और मैच्योर या बड़ों की तरह व्यवहार करें। इसके बाद सलमान ने अली गोनी से पूछा कि उन्होंने स्थिति को क्यों नहीं समझा और जैस्मीन को समझाया क्यों नहीं। घरवालों से नाराज सलमान ने कहा कि हर कोई सिर्फ इसलिए गलत व्यवहार करता है क्योंकि राखी का एक अलग तरह का व्यक्तित्व है और वह अंग्रेजी को अच्छी तरह से नहीं बोल पाती हैं। सलमान खान ने फिर राखी को परेशान करने के लिए रुबीना दिलैक को भी जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि वह राखी को नीचा दिखाती हैं क्योंकि उन्हें ये कूल लगता है। उन्होंने रुबीना को उंगुली दिखाने वाली हरकत के लिए भी फटकार लगाई। सलमान ने राखी को लेकर खुलासा किया कि उन्हें चोट लगी है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स की मानें तो बहुत सीरियस इंजरी नहीं है मगर चूंकि राखी ने सर्जरी करवाई है तो इसलिए उन्हें डॉक्टर्स से चेकअप और स्कैन करवाना होगा। उसके लिए उन्हें 14 दिन बिग बॉस के घर से बाहर रहना पड़ेगा।

84 के दंगों पर फिल्म में नजर आएंगे दिलजीत दोसांझ

दिलजीत दोसांझ बॉलीवुड के उभरते हुए सितारों में से एक है। उनके पास इस समय कई बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स है। हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने घोषणा की कि उनकी पंजाबी फिल्म 'जोड़ी' 2021 में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब खबर आ रही है कि दिलजीत के हाथ एक और बड़ी फिल्म लग गई है। खबरों के अनुसार दिलजीत दोसांझ निर्देशक अली अब्बास जफर संग एक फिल्म में काम करने जा रहे हैं। अली अब्बास की यह फिल्म 1984 में हुए सिख दंगों पर आधारित बताई जा रही है। इस फिल्म में दिलजीज दोसांझ एक दम सिंपल लुक में नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि ये अली अब्बास जफर का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वे इसे बड़े स्केल पर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक 84 के दंगों पर बन रही इस फिल्म में पहले से ही दिलजीत को लेने का मन बनाया गया था। अब क्योंकि एक्टर भी एक पंजाबी हैं, ऐसे में वे किरदार संग न्याय कर पाएंगे। खबरों के अनुसार चूंकि यह एक पीरियड ड्रामा है और 80 के दशक से जुड़ा है तो उसके सेट के लिए कई विशेष डिटेल्स ली जा रही हैं। इस सेट में एक चॉल और दो मंजिला इमारत शामिल होंगी। अली अब्बास जफर 9 जनवरी तक इस फिल्म को रोल करने की योजना बना रहे हैं।

एक्शन-थ्रिलर सीरीज के साथ डिजिटल दुनिया में एंट्री करेंगे रोहित शेट्टी

रोहित शेट्टी एक्शन से भरी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। अब वे ऐसी ही एक वेब सीरिज के साथ डिजिटल दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। दिग्गज स्टंटमैन एम बी शेट्टी के बेटे रोहित सिंघम, सिंबा, गोलमाल, चेन्नई एक्सप्रेस और आल द बेस्ट जैसी फिल्मों के लिए मशहूर हैं। रोहित शेट्टी एक्शन-एडवेंचर शो 'फियर फैक्टर : खतरों के खिलाड़ी' के साथ टीवी जगत में भी प्रवेश कर चुके हैं। अब वे डिजिटल दुनिया में भी कदम रखने के लिए तैयार है। एक सूत्र ने बताया, रोहित आठ एपिसोड की एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज बनाने वाले हैं। यह सत्य घटनाओं से प्रेरित होगी। सीरीज के शीर्षक को लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। रोहित फिलहाल अपनी फिल्म सर्कस को लेकर व्यस्त हैं जिसमें वे रणवीर सिंह के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म विलियम शेक्सपियर के नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित है।

तापसी पन्नू ने बताया सही कॉन्फिडेंस क्या होता है

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वह अक्सर खुद से जुड़ी हर अपडेट शेयर करती रहती हैं। उन्होंने अब अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए 'कॉन्फिडेंस' को लेकर दिलचस्प पोस्ट की है। तापसी पन्नू ने बताया कि सही 'कॉन्फिडेंस' क्या होता है? तापसी की यह पोस्ट फैंस को बेहद पसंद आ रही है। तस्वीर में तापसी राउंडेड धूप का चश्मा पहने एक ग्रे रंग की ड्रेस में दिखाई दे रही हैं, जिसमें उनके बाल खुल हुए हैं। उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, 'कॉन्फिडेंस' एक कमरे में नहीं चल रहा है यह सोचकर कि आप हर किसी से बेहतर हैं। आप कभी किसी से पहली बार मिल कर उससे खुद की तुलना न करें। हैप्पी संडे।' तापसी की पोस्ट पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो तापसी पन्नू फिल्म 'रश्मि रॉकेट' में नजर आएंगी। फिल्म में वह एक धावक की भूमिका में हैं। इसके अलावा तापसी की आने वाली फिल्म 'लूप लपेटा' की शूटिंग भी जोरों पर चल रही है। फिल्म में ताहिर राज भसीन भी अहम किरदार में हैं।

कुली नंबर 1 की आलोचना करने वालों को वरुण ने दिया जवाब

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर फिल्म 'कुली नंबर 1' पिछले साल 25 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इसे ओटीटी प्लैटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिलीज होने के बाद इसे काफी निगेटिव फीडबैक मिला। सोशल मीडिया पर कुली नंबर 1 को लेकर फनी मीम बनने लगे, वरुण के सीन्स का मजाक उड़ाया गया और सारा की एक्टिंग पर भी तंज कसे गए। हाल ही में फिल्म की आलोचना को लेकर वरुण धवन से बातचीत की गई, जिस पर एक्टर ने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर चीज तो हिट नहीं हो सकती है न। एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में वरुण धवन ने कहा, चीजें करना मुश्किल होता है। जिंदगी से भी कई चीजें बड़ी होती हैं। उन चीजों के प्रति आपके अंदर सहनशीलता होनी जरूरी होती है। मैं एंजॉय करता हूं। मेरे लिए एक फिल्म बनाना मतलब सभी को प्लीज करना होता है। जनता का रिएक्शन मेरे लिए काफी मायने रखता है। वरुण आगे कहते हैं, मैं फेक हो सकता हूं और कूल बनने की भी कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि मेरी फिल्म ओटीटी पर है। यह मेरी ऑडियंस है और मैं इसी के लिए काम करता हूं। जो कोई कहता है कि मैं कूल नहीं हूं, क्योंकि मैं कई खराब फिल्में भी करता हूं तो ठीक है मैं कूल नहीं हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता है।

अनिल कपूर का खुलासा कपिल शर्मा ने ठुकराएं उनकी फिल्मों के ऑफर

बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'इख फ्प इख' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में वह अपनी इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए 'द कपिल शर्मा शो' में पहुंचे। यहां उन्होंने कपिल शर्मा के साथ जमकर मस्ती तो की ही, साथ ही कई किस्से भी सुनाए। अनिल कपूर ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी कई फिल्मों के लिए कपिल को ऑफर दिए, जिसके लिए उन्होंने हर बार इंकार कर दिया। अनिल कहते हैं, मैंने आपको इतनी फिल्में ऑफर की, लेकिन आप हर बार मना कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? इस पर कपिल कहते हैं, अनिल सर ने मुझे '24' सीरीज के लिए ऑफर दिया था, लेकिन तब हमारा शो नया-नया शुरू हुआ तो। इस पर अनिल कहते हैं, आपने मुझे बताया था। अच्छा हुआ आपने '24' नहीं किया। कपिल कहते हैं, आपने मुझे 'वो सात दिन' दोबारा बनाने के लिए कहा था। अनिल ने बताया, आपको 'मुबारकां' ऑफर हुई। फिर मैं प्रियदर्शन के साथ एक फिल्म कर रहा हूं 'तेज' उसे भी आपने मना कर दिया। अनिल कपूर ने कहा, अब वह सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं, वह किसी फिल्म में कपिल के भाई या पिता बन सकते हैं। इस पर कपिल ने कहते हैं, ऐसा न हो कि पर्दे पर अनिल के सामने वही पिता दिखने लगे। अनिल कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म 'तख्त' में नजर आएंगे। वह राज मेहता की 'जुग जुग जियो' और संदीप रेड्डी वांगा की 'एनिमल' में भी दिखेंगे।

धूम 4 में नजर आ सकती हैं दीपिका

यशराज फिल्म्स की एक्शन फ्रेंचाइजी 'धूम' की चौथी फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा कारोल तो हमेशा फिक्स माना जाता है, लेकिन विलेन हर बार कोई दूसरा होता है। 'धूम 4' को लेकर सामने आई खबरों की मानें तो इसमें दर्शकों को मेल चोर नहीं बल्कि फीमेल चोर नजर आएंगी। खबरों के अनुसार यशराज बैनर ने 'धूम 4' में दीपिका पादुकोण को स्टाइलिश चोरनी के रूप में पेश करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण और यशराज बैनर के बीच लगातार बातचीत जारी है और इस समय दीपिका पादुकोण शूटिंग डेट्स को अपने कैलेंडर में फिट करने की कोशिश कर रही हैं। अगर सबकुछ ठीक रहता है कि 'धूम 4' की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। दीपिका पादुकोण ने अपने करियर में कई बार एक्शन किया है, लेकिन माना जा रहा है कि 'धूम 4' का एक्शन उनके फैंस को चौंकाकर रख देगा। इसमें वो हॉलीवुड स्तर के एक्शन सीन्स फिल्माती दिखेंगी। बता दें कि यशराज बैनर की 'धूम' सीरीज बॉलीवुड की पहली सफल फ्रेंचाइजी है, जिसकी पहली तीनों फिल्मों को दर्शकों का खूब सारा प्यार मिला है। अब तक दर्शक जॉन अब्राहम, रितिक रोशन और आमिर खान को इस फ्रेंचाइजी में चोर का किरदार निभाते देख चुके हैं।

मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के लिए मुख्यकार्यकारी ने खिलाड़ियों से सभी कुछ ठीक होने की बात कही।

सिडनी में 42 साल के जीत के सूखे को समाप्त करने उतरेगी टीम इंडिया

सिडनी, (एजेंसी)। मेलबर्न में मिली जीत से उत्साहित टीम इंडिया गुरुवार को यहां मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू होने वाले तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त दर्ज करने उतरेगी। चार टेस्ट मैचों की यह सीरीज अभी 1- 1 से बराबरी पर है। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने एडीलेड में पहला टेस्ट जीता था पर इसके बाद भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट जीतकर शानदार वापसी की है। टीम इंडिया के कप्तान आजिंक्य रहाणे शानदार फार्म में हैं और दूसरे टेस्ट में उन्होंने जिस प्रकार शानदार कप्तानी की थी उस सिलसिले को वह इस बार भी बरकरार रखना चाहेंगे। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की वापसी से भी टीम की बल्लेबाजी मजबूत होगी। रोहित को उपकप्तानी की जिम्मेदारी भी दी गयी है। ऐसे में वह शानदार प्रदर्शन कर अपने चयन को सही साबित करना चाहेंगे। रोहित को फिट नहीं होने के कारण पहले दोनो टेस्ट के लिए शामिल नहीं किया गया था। उन्हें तीसरे टेस्ट के लिए उन्हें मयंक अग्रवाल की जगह शामिल किया गया है। मयंक ने पहले दोनो मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, ऐसे में उन्हें हटाया जाना तय नजर आ रहा था। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो वहीं तेज गेंदबाज उमेश यादव की जगह नवदीप सैनी को शामिल किया गया है। नवदीप इस मैच से अपना टेस्ट पदार्पण करेंगे। उमेश यादव चोटिल होने के कारण सीरीज से ही बाहर हो गये हैं। नवदीप के पास अब इस मैच में अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है। भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन इस सीरीज में अब तक अच्छा रहा है और उन्होंने कंगारुओं को खुलकर खेलने का अवसर नहीं दिया है। गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराज के पास रहेगी वहीं स्पिन की जिम्मेदारी रविन्द्र जडेजा और अनुभवी आर अश्विन पर रहेगी।

रहाणे अगर इस सीरीज में टीम इंडिया को जीत दिलाने में सफल रहते हैं तो वह 42 साल बाद इस मैदान पर टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले पहले कप्तान बन जायेंगे। इससे पहले साल 1978 में बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में टीम इंडिया ने यहां जीत दर्ज की थी। ऐडिलेड में मिली करारी हार के बाद जिस तरह भारतीय टीम ने मेलबर्न में वापसी की उससे मेजबान टीम भी दबाव में है।

वहीं आंकड़ों पर गौर करें तो सिडनी में भारतीय टीम का रेकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। मेजबान टीम का रेकॉर्ड इस मैदान पर भारत के खिलाफ बहुत अच्छा है। अपने पिछले दौरे में भारतीय टीम ने ऋषभ पंत के शतक की सहायता से 7 विकेट पर 622 रन बनाए थे। इसके बाद कुलदीप यादव ने पांच विकेट लेकर भारतीय टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया था हालांकि तब बारिश के कारण भारतीय टीम जीत दर्ज नहीं कर पायी थी और मैच ड्रॉ रहा। भारतीय टीम इस बार भी पिछली बार जैसा प्रदर्शन करना चाहेगी। सिडनी में इस प्रकार का रहा है भारतीय टीम का प्रदर्शन।

भारतीय टीम ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर अपनी एकमात्र जीत 1978 को हासिल की थी। अब रहाणे की कप्तानी वाली टीम इस मैदान पर एक और जीत दर्ज करना चाहेगी।

भारतीय टीम ने इस मैदान पर 12 टेस्ट मैच खेले हैं और केवल एक मैच जीता है। इस ऐतिहासिक मैदान पर दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों में पांच मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया है जबकि छह मैच ड्रॉ रहे हैं।

इस मैदान पर भारत के सबसे सफल बल्लेबाजों में सचिन तेंडुलकर सबसे आगे हैं। सचिन ने इस मैदान पर 785 रन बनाए हैं। इसमें तीन शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने भारत की ओर से इस मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में 20 विकेट लिए हैं।

तीसरे मैच के लिए टीम इंडिया ने अपने अंतिम ग्यारह खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। टीम में मयंक की जगह रोहित को शामिल किया गया है। इसके अलावा नवदीप अपना डेब्यू करेंगे। युवा बल्लेबाज मयंक को पहले दोनो मैचों में खराब प्रदर्शन के कारण बाहर कर दिया गया है। रोहित को अंतिम ग्यारह में शामिल करने के साथ ही बाकी दोनो मैचों के लिए उपकप्तान बनाया गया है। वहीं तेज गेंदबाज सैनी अपने टेस्ट करियर की शुरूआत करेंगे।

वहीं दूसरी और मेजबान टीम भी इस मैच में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर की वापसी से टीम की बल्लेबाजी बेहतर होगी। इसके अलावा उसके पास कप्तान टिम पेन और मार्नस लाबुशेन जैसे बल्लेबाज हैं। तेज गेंदबाजी में टीम के पास मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस जबकि स्पिनर के तौर पर अनुभवी नाथन लियोन हैं।

टीम इंडिया इस प्रकार है। अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और नवदीप सैनी।

आस्ट्रेलिया : डेविड वार्नर, मैथ्यू वेड, विल पुकोवस्की, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, कैमरन ग्रीन, टिम पेन (कप्तान और विकेटकीपर), नाथन लियोन, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, मार्कस हैरिस, मिशेल स्वेपसन, माइकल नेसर।

संक्षिप्त समाचार

एल्गर के बयान से सोशल मीडिया पर कुशल हुए ट्रॉल

क्राइस्टचर्च, (एजेंसी)। श्रीलंकाई बल्लेबाज कुशल परेरा दक्षिण अफ्रीकी दौरे में नाकाम रहे और 3 पारियों में खाता तक नहीं खोल पाये। इस कारण श्रीलंका को दूसरे टेस्ट में करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं मैन ऑफ द सीरीज बने डीन एल्गर ने मैच के बाद एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुशल ट्रॉल होने लगे। एल्गर ने कहा, टीम में उनको कुशल कहा जा रहा था जबकि मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा है। एल्गर ने कहा, मैं नहीं कह सकता कि पहले टेस्ट में शतक न लगा पाना बेहद निराशाजनक था। मैं केवल अपने बेहतर हाल में लाना चाहता था। मुझे पता था कि अगर मैंने कब्जा कर लिया और कड़ी मेहनत की तो मैं दूसरे टेस्ट में अच्छा स्कोर खड़ा कर सकता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि स्विंग होगी। मुझे यह बेहद पसंद है।

जैमीसन ने प्रशंसक के सिर पर दिया ऑटोग्राफ

वेलिंग्टन, (एजेंसी)। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच में शानदार प्रदर्शन के साथ ही एक प्रशंसक के सिर पर ऑटोग्राफ देकर भी सबका ध्यान खींचा है। मैच के पहले दिन जब पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो उस दौरान जैमीसन बाउंड्री के पास फिल्डिंग कर रहे थे। इस दौरान उनसे एक दर्शन ने जब ऑटोग्राफ मांगा तो वह उसे मना नहीं कर पाए पर उस दर्शक ने जिस जगह जैमीसन का ऑटोग्राफ मांगा वह बेहद मजेदार था। दर्शक ने ऑटोग्राफ के लिए अपने सिर को आगे किया जिस पर जैमीसन ने ऑटोग्राफ दिया। इससे भी मजेदार बात यह रही कि तीन दिन बाद भी उस दर्शक के सिर पर जैमीसन के ऑटोग्राफ हैं।

धनश्री ने शेयर किया शादी से पहले का डांस वीडियो

नई दिल्ली, (एजेंसी)। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा ने अब एक डांस वीडियो शेयर किया है जिसमें वह माधुरी दीक्षित की फिल्म के एक गाने अरे रे अरे ये क्या हुआ गाने पर ठुमके लगाते नजर आई। धनश्री ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया है। ये वीडियो शादी से पहले का है क्योंकि धनश्री इस दौरान शादी के जोड़े में नजर आ रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए धनश्री ने लिखा, सभी दुल्हनें जो बाहर हैं डांस करें। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, मिसेज चहल बनने से पहले एक क्विक डांसिंग सेशन। धनश्री के इस डांस वीडियो को 3 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और सैकड़ों लोगों ने इस पर कमेंट्स भी किए।

आकिब जावेद ने मिसबाह पर निशाना साधा

कराची, (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज आकिब जावेद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली करारी हार के लिए कोच मिसबाह उल हक को जिम्मेदार बताया है। आकिब ने मिसबाह को आड़े हाथों लिया और कहा कि वह राष्ट्रीय टीम तो क्या किसी स्कूल टीम के कोच बनने लायक भी नहीं हैं। पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) की फ्रैंचाइजी लाहौर कलंदर्स के मुख्य कोच आकिब ने कहा कि मिसबाह कोच बनने के लिए सही नहीं हैं। जावेद ने कहा, मुझे लगता है कि जिसने मिसबाह और वकार यूनिस को कोच नियुक्त किया उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों ही पूर्व खिलाड़ियों के पास कोचिंग का कोई अनुभव नहीं है। न्यूजीलैंड में मिली हारों के बाद पाक क्रिकेटरों को कड़ी आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। इससे पहले पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इसे क्लब स्तर की टीम बताया था।

टेनिस कोच बॉब का निधन

मेलबर्न, (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के लोकप्रिय टेनिस कोच बॉब ब्रेट का निधन हो गया है। बॉब 67 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से कैंसर से पीड़ित थे। वह बोरिस बेकर, गोरान इवानिसेविच और मारिन सिलिच जैसे दिग्गज टेनिस खिलाड़ियों के कोच रहे हैं। टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने उनके निधन पर शोक व्यक्त कतरे हुए उन्हे श्रद्वांजलि दी है। टेनिस ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी क्रेग टिले ने कहा, बॉब ब्रेट का निधन टेनिस के लिये बहुत बड़ा नुकसान है। वह बेजोड़ कोच थे। उन्होंने ग्रैंडस्लैम चैंपियन से लेकर इस खेल में शुरूआत करने वाले खिलाड़ी सभी को सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभायी थी।

शशिकिरण ने रिल्टन कप शतरंज जीता

चेन्नई, (एजेंसी)। भारत के कृष्णन शशिकिरण नें रिल्टन कप ऑनलाइन शतरंज टूनार्मेंट जीत लिया है। यह इस दशक और साल 2021 मे किसी भी भारतीय खिलाड़ी का पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब है। शशिकिरण ने खिताबी मुकाबले में रूस के अलेक्जेंडर शिमानोव को 2-0 से हराया। स्टाकहोम शतरंज संघ द्वारा आयोजित इस टूनार्मेंट में कुल 16 प्रतियोगियों के बीच नॉक आउट आधार पर हुए टूनार्मेंट में 4 चरणों को पार करते हुए उन्होने यह जीत दर्ज की। सबसे पहले उन्होने उक्रेन के मिखाइल गुरेविच को 3-2 से हराकर क्वाटर फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद क्वाटर फाइनल में उन्होने रूस के यूरी याकोविच को 3-2 से हराया, सेमी फाइनल में शशि नें स्वीडन के राल्फ अकेस्सोन को 1.5-0.5 से शिकस्त देते हुए फाइनल में जगह बनायी।

पाक टीम और पीसीबी पर भड़के अख्तर

औसत खिलाड़ियों के साथ क्लब टीम जैसी बनी राष्ट्रीय टीम

करांची, (एजेंसी)। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने निशाना साधा है। अख्तर ने कहा है कि पाक का प्रदर्शन किसी क्लब टीम जैसा है। अख्तर ने पाक बोर्ड पर अपनी नाराजगी जाहिर करते उनकी नीति पर सवाल उठाए और कहा कि उसने जो बोया है, वो काट रहा है।

इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि पाक टीम का वह क्लब टीम इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि इनको टीम में ऐसे बच्चे चाहिए थे, जो बीच में से मांग निकालकर, बाल सीधे करके और आंखों में सूरमा लगाकर स्कूल भेज जाते हैं। उन्होंने कहा कि न तो टीम में और न ही प्रबंधन में परिपक्वता नजर आई। न्यूजीलैंड में दो पारी के बाद खिलाड़ी समझ जाते हैं कि वहां पर गेंद को तैराना होता है, मगर पाक टीम में ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। इसी लिए टेस्ट में अनुभव होना चाहिए।

अख्तर ने पाक बोर्ड पर अपनी नाराजगी जाहिर करते उनकी नीति पर सवाल उठाए और कहा कि उसने जो बोया है, वो काट रहा है। उन्होंने कहा कि औसत खिलाड़ी लाते रहेंगे, औसत खिलाड़ी खिलाते रहेंगे। औसत टीम बनाते रहेंगे, औसत ही रिजल्ट आते हैं और औसत ही काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाक जब भी टेस्ट क्रिकेट खेला, तब तब उसकी पोल खुलती रहेगी। ये लोग स्कूल स्तर की क्रिकेट खेल रहे हैं और प्रबंधन ने खिलाड़ियों को स्कूल स्तर का क्रिकेटर बना दिया है। उन्होंने कहा कि कितने चेयरमैन आए और गए। देश का क्रिकेट बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा तब तक रहेगा, जब कि औसत खिलाड़ी आते रहेंगे।

हितों के टकराव मामले में फंसे सकते हैं विराट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हितों के टकराव मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। विराट ने फरवरी 2019 में एक कंपनी में निवेश किया था, वहीं यह कंपनी अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की आधिकारिक साझेदार बन गयी है। यह कंपनी किट प्रायोजक है। भारतीय टीम के कप्तान को बेंगलुरू स्थित कंपनी गैलेक्टस फनवेयर टेक्नोलॉजी ने 33.32 लाख रुपये कंपलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (सीसीडी) आवंटित किए हैं। यह कंपनी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) का मालिकाना हक रखती है और विराट इसके ब्रांड एंबेडसर हैं। 17 नवंबर 2020 को बीसीसीआई ने एमपीएल स्पोर्ट्स को टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर और आधिकारिक व्यापारिक साझीदार घोषित किया था। इसके तहत भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीम और अंडर 19 टीम एमपीएल जर्सी को सपोर्ट करेंगे। टीम इंडिया की जर्सी के अलावा एमपीएल स्पोर्ट्स लाइसेंस प्राप्त टीम इंडिया के दूसरे सामान को भी बेच पाएंगे। कोहली को जनवरी 2020 में एमपीएल का ब्रांड एंबेडसर बनाया गया था। उन्होंने पहले भी गेमिंग प्लेटफॉर्म का समर्थन किया था।

वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार, जब फरवरी 2019 में कोहली को गैलेक्टस कंपनी ने सीसीडी जारी किए थे तो उन्होंने कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को भी 16.66 लाख रुपये के 34 सीसीडी जारी किए थे। कॉर्नरस्टोन के सीईओ अमित अरुण सजदेह कप्तान कोहली के साथ दो अन्य फर्म में भी भागीदार हैं जिसका नाम मैग्पी वेंचर्स पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड और विराट कोहली स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। इसके अलावा सजदेह और कोहली का एक और लिंक है. कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसमें सजदेह डायरेक्टर हैं वह कोहली के कर्मशियल राइट्स का प्रबंधन करती है।

न्यूजीलैंड ने पाक को एक पारी और 186 रनों से हराया, आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची

क्राइस्टचर्च, (एजेंसी)। न्यूजीलैंड ने मेहमान टीम पाकिस्तान को यहां खेले गये दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 176 रनों से हराया है। मैच के चौथे दिन ही पाक टीम अपनी दूसरी पारी में 186 रनों पर ही आउट हो गयी। मेजबान न्यूजीलैंड ने इस प्रकार दो टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीतने के साथ ही आईसीसी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं अब तक नंबर एक पर रही ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर खिसक गयी है। आईसीसी की ताजा टेस्ट टीमों की रैंकिंग में न्यूजीलैंड पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे जबकि भारतीय टीम तीसरे नंबर पर है। इस मैच में मजबान टीम पूरे समय हावी रही उसने टॉस जीतकर पाक को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। पाक की टीम अपनी की पहली पारी में 297 रनों पर ही आउट हो गयी। पाक की ओर से अजहर अली ने 93 और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 61 रनों की पारी खेली।

वहीं पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज काइल जेमीसन ने दूसरी पारी में भी छह विकेट लिए। न्यूजीलैंड की ओर से इस मैच में कप्तान केन विलियमसन ने 238 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। । इस मैच में घातक गेंदबाजी कर कीवी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले काइल जेमीसन को मैन ऑफ द मैच और केन विलियमसन को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है।

इसके बाद न्यूजीलैंड ने विलियमसन के रिकार्ड दोहरे शतक की सहायता से अपनी पहली पारी छह विकेट पर 659 रन बनाकर घोषित कर दी। विलियमसन ने 238, हेनरी निकोल्स ने 157 और डेरेल मिचेल ने नाबाद 102 रन बनाये। वहीं पाक की ओर से शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अब्बास और फहीम अशरफ ने दो-दो विकेट लिए। पहली पारी के आधार पर 362 रनों से पिछड़ने के बाद पाक टीम अपनी दूसरी पारी में कीवी बल्लेबाजों के सामने टिक नहीं पायी और 186 रनों पर ही सिमट गयी। पाक की ओर से दूसरी पारी में केवल अजहर अली और जफर गोहर ही 37-37 रनों की पारियां खेल पाये बाकि बल्लेबाज सस्ते में ही सिमट गये।

ब्रिस्बेन टेस्ट बदलने की मांग से पैदा हुआ तनाव : पेन

सिडनी, (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने माना है कि भारतीय टीम ने ब्रिस्बेन में होने वाले चौथे टेस्ट मैच का स्थल बदलने की जो मांग की है उससे दोनो टीमों के बीच एक प्रकार का तनाव पैदा हो गया है। टेन ने कहा कि गुरुवार हो शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले भारतीय टीम ने क्वीन्सलैंड प्रांत के स्वास्थ्य संबंधी कड़े नियमों के कारण ब्रिस्बेन में खेलने का इंकार कर दिया। भारतीय टीम का कहना है कि क्वीन्सलैंड के प्रोटोकॉल के अनुसार भारतीय खिलाड़ी टेस्ट मैच के दौरान अपने कमरों से भी बाहर नहीं निकल सकते और उन्हें एक प्रकार से पृथकवास में रहना होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने यह मामला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के सामने भी रखा जिसके बाद पता चला है कि अब खिलाड़ियों को होटल के अंदर जैव सुरक्षित वातावरण और टेस्ट मैच में आपस में मिलने की अनुमति दे दी गई है।

पेन से जब पूछा गया कि मेलबर्न क्रिकेट मैदान में ऋषभ पंत और मैथ्यू वेड के बीच छींटाकशी के अलावा अब तक इस तरह की घटना नहीं होने का क्या कारण है, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब उबाल आने वाला था क्योंकि कुछ चीजें होने जा रही थी। उन्होंने कहा, यह क्रिकेट की नजर से ही महत्वपूर्ण नहीं होगा बल्कि टीम के अंदर भी इसको लेकर रोष होगा क्योंकि उनकी (भारतीय) तरफ से कई अज्ञात सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि वे चौथा टेस्ट मैच कहां खेलने जा रहे हैं, वे कहां नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है।

क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के गेंदबाज केली जेमीसन को बल्लेबाज शान मसूद का विकेट लेने पर बधाई देते हुए टीम के साथी खिलाड़ी।